गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD, SURAT, LUCKNOW

वर्ष : 16
अंक : 155
दि. 04.10.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

इंडो-पैसिफिक में भारत की समुद्री ताकत का विस्तार, ASEAN के साथ बढ़ा नौसैनिक सहयोग

सुबिक बे। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में तेजी से बदलते समुद्री और सामरिक समीकरणों के बीच भारत ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने नौसैनिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। फिलीपींस के सुबिक बे में आयोजित दूसरे आसियान-भारत समुद्री अभ्यास AIME-2026 में भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस सह्याद्रि और आईएनएस कुलिश हिस्सा ले रहे हैं। आसियान सदस्य देशों की समुद्री सेनाओं के साथ आयोजित यह बहुपक्षीय अभ्यास आपसी समझ, परिचालन समन्वय और संयुक्त रूप से समुद्री अभियानों को संचालित करने की क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। भारत के लिए यह अभ्यास उसकी एक्ट ईस्ट नीति और महासागर दृष्टिकोण के तहत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री साझेदारियों को विस्तार देने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

AIME-2026 का दूसरा संस्करण 28 सितंबर को सुबिक बे में शुरू हुआ। अभ्यास की थीम 'विश्वास में अटूट, समुद्र में एकजुट' रखी गई है, जो भारत और आसियान देशों के बीच समुद्री सहयोग के मूल उद्देश्य को रेखांकित करती है। अभ्यास के दौरान पेशेवर, परिचालन और सामाजिक स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य भाग लेने वाली नौसैनिक सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और आपसी विश्वास विकसित करना है। भारतीय नौसेना के दोनों युद्धपोत इससे पहले भी इसी क्षेत्र में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस से संबंधित समुद्री सुरक्षा गतिविधियों में हिस्सा ले चुके हैं। इससे दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत की बढ़ती नौसैनिक भागीदारी का संकेत मिलता है।

अभ्यास का शुरुआती चरण सुबिक बे में बंदरगाह आधारित गतिविधियों पर केंद्रित है। इस दौरान विभिन्न देशों के नौसैनिक अधिकारियों और विशेषज्ञों के बीच समुद्री सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श, परिचालन संबंधी समन्वय और अनुभवों का आदान-प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से भी भाग लेने वाले देशों के नौसैनिक कर्मियों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में इस

तरह की गतिविधियां केवल औपचारिक नहीं होतीं, बल्कि अलग-अलग देशों की कार्यप्रणाली को समझने और भविष्य में संयुक्त अभियानों के दौरान बेहतर तालमेल स्थापित करने में उपयोगी साबित होती हैं।

बंदरगाह चरण के बाद अभ्यास का समुद्री चरण आयोजित किया जाएगा, जिसमें भाग लेने वाली नौसेनाएं विभिन्न समन्वित समुद्री गतिविधियों में हिस्सा लेंगी। इसका उद्देश्य वास्तविक समुद्री परिस्थितियों में अलग-अलग देशों की नौसेनाओं के बीच परिचालन तालमेल को परखना और मजबूत करना है। समुद्र में किसी संकट, प्राकृतिक आपदा, मानवीय सहायता अभियान या अन्य आपात स्थिति के दौरान अलग-अलग देशों की नौसेनाओं को सीमित समय में एक-दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करना पड़ सकता है। ऐसे बहुपक्षीय अभ्यास इसी प्रकार की परिस्थितियों में संयुक्त कार्रवाई की क्षमता विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं।

भारत की समुद्री रणनीति का दायरा पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर क्षेत्र से आगे बढ़कर व्यापक इंडो-पैसिफिक तक पहुंचा है। आसियान देश इस रणनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि भारत के पूर्वी समुद्री पड़ोस में स्थित इन देशों के साथ व्यापार, समुद्री संपर्क और सुरक्षा संबंध सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। भारत के लिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा केवल रक्षा से संबंधित विषय नहीं है, बल्कि इसका संबंध व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, आपदा राहत और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों से भी है। ऐसे में आसियान देशों के साथ नौसैनिक सहयोग को भारत की व्यापक क्षेत्रीय भागीदारी के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार AIME-2026 भारत की एक्ट ईस्ट नीति और महासागर दृष्टिकोण के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है। एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर लगातार जोर देता रहा है। समुद्री क्षेत्र इस नीति का एक महत्वपूर्ण आयाम है। हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक के बीच समुद्री संपर्क भारत तथा आसियान देशों के व्यापार और रणनीतिक हितों को आपस में जोड़ता है।

AIME-2026 का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर विभिन्न देशों की सक्रियता बढ़ी हुई है। विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में समुद्री गतिविधियां और क्षेत्रीय दावे लंबे समय से चर्चा का विषय रहे हैं। चीन की बढ़ती नौसैनिक और समुद्री सक्रियता के बीच फिलीपींस समेत क्षेत्र के कई देशों के लिए समुद्री सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि AIME-2026 को आधिकारिक तौर पर किसी एक देश के खिलाफ केंद्रित अभ्यास के रूप में पेश नहीं किया गया है। इसका घोषित उद्देश्य भारत और आसियान देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग, परिचालन समन्वय और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है।

भारत की ओर से आईएनएस सह्याद्रि और आईएनएस कुलिश की भागीदारी इस समुद्री साझेदारी को व्यावहारिक स्तर पर आगे बढ़ाने का संकेत देती है। संयुक्त अभ्यास के दौरान अलग-अलग नौसेनाओं को एक-दूसरे की प्रक्रियाओं, संचार प्रणालियों और परिचालन तौर-तरीकों को समझने का अवसर मिलता है। इससे भविष्य में समुद्री सुरक्षा से जुड़ी साझा परिस्थितियों में बेहतर समन्वय स्थापित करने की क्षमता विकसित हो सकती है।

भारतीय नौसेना की गतिविधियां अब केवल भारतीय समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा तक सीमित नहीं हैं। मित्र और साझेदार देशों के साथ संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण, बंदरगाह यात्राएं और समुद्री सुरक्षा गतिविधियां भारत की व्यापक समुद्री पहुंच का हिस्सा बनती जा रही हैं। आसियान देशों के साथ बढ़ता सहयोग इसी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत का जोर ऐसे समुद्री वातावरण पर है जिसमें क्षेत्रीय देश साझा चुनौतियों से निपटने के लिए एक-दूसरे की क्षमताओं का उपयोग कर सकें और संकट के समय प्रभावी समन्वय कायम कर सकें। महासागर दृष्टिकोण के तहत भी भारत समुद्री क्षेत्र में साझेदारी, क्षमता निर्माण और साझा सुरक्षा हितों को महत्व देता है। AIME-2026 जैसे अभ्यास इस दृष्टिकोण को व्यावहारिक रूप देने का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसमें सैन्य प्रशिक्षण के साथ-साथ पेशेवर संपर्क और आपसी विश्वास को भी महत्व दिया जा रहा है। इससे भारत और आसियान देशों के बीच समुद्री सहयोग केवल औपचारिक संवाद तक सीमित न रहकर परिचालन स्तर तक पहुंचता है।

सुबिक बे में भारतीय नौसेना की मौजूदगी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फिलीपींस इंडो-पैसिफिक के ऐसे समुद्री क्षेत्र में स्थित है, जहां समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दे लगातार प्रमुख बने हुए हैं। भारत फिलीपींस समेत आसियान देशों के साथ अपने समुद्री संबंधों को मजबूत करते हुए क्षेत्रीय साझेदारी का दायरा बढ़ा रहा है। AIME-2026 इसी व्यापक प्रक्रिया की एक कड़ी है।

कुल मिलाकर AIME-2026 को भारत की समुद्री कूटनीति, एक्ट ईस्ट नीति और इंडो-पैसिफिक भागीदारी के संदर्भ में देखा जा सकता है। इस अभ्यास के जरिए भारत और आसियान देशों की नौसेनाओं को एक साथ प्रशिक्षण और परिचालन अनुभव साझा करने का अवसर मिल रहा है। बदलते समुद्री वातावरण में ऐसे बहुपक्षीय अभ्यास आपसी विश्वास, समन्वय और संकट के समय संयुक्त प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने में भूमिका निभा सकते हैं। सुबिक बे में आईएनएस सह्याद्रि और आईएनएस कुलिश की भागीदारी भारत की उस व्यापक रणनीति को भी रेखांकित करती है, जिसमें समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को इंडो-पैसिफिक नीति के महत्वपूर्ण आधार के रूप में देखा जा रहा है।

योम किप्पुर से पहले मैनचेस्टर में हमले की साजिश का आरोप, दो ईरानी नागरिक गिरफ्तार

लंदन। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर कथित आतंकी हमला करने की साजिश का मामला सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हलचल बढ़ गई है। काउंटर टेररिज्म पुलिस ने दो ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार कर उन पर आतंकवादी गतिविधि की तैयारी से जुड़े आरोप लगाए हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपियों ने यहूदी समुदाय से जुड़े संभावित ठिकानों की रेकी करने के साथ विस्फोटक उपकरण तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और उपकरण जुटाए थे। पुलिस के मुताबिक, कथित साजिश योम किप्पुर से पहले हमले की तैयारी से जुड़ी थी। दोनों आरोपियों को 20 सितंबर को मैनचेस्टर में गिरफ्तार किया गया था और 2 अक्टूबर को उनके खिलाफ औपचारिक आरोप लगाए गए।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 36 वर्षीय सलाम अहमद्यान और 34 वर्षीय रहमान सालेही के रूप में हुई है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि दोनों ने कथित तौर पर घरेलू स्तर पर विस्फोटक उपकरण तैयार करने की दिशा में तैयारी की और इसके लिए आवश्यक सामान एकत्र किया। इसके साथ ही संभावित हमले के स्थानों की निगरानी और रेकी किए जाने का भी दावा किया गया है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा कि जांच के दौरान मैनचेस्टर के यहूदी संग्रहालय और हीटन पार्क सिनेगॉग जैसे स्थानों को संभावित निशाने के रूप में चिन्हित किए जाने की बात सामने आई।

मामले में जांच एजेंसियों ने विदेश में मौजूद एक तीसरे व्यक्ति की भूमिका की भी जांच शुरू की है। काउंटर टेररिज्म पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों के संपर्क में एक अन्य व्यक्ति था, जिसके ईरान में मौजूद होने की आशंका है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में आरोप लगाया कि इस व्यक्ति ने कथित तौर पर हमले से संबंधित निर्देश और घरेलू विस्फोटक उपकरण तैयार करने के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। हालांकि, जांच एजेंसियां इस संपर्क और कथित भूमिका से जुड़े साक्ष्यों की जांच कर रही हैं। अदालत में लगाए गए आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं और मामले की न्यायिक प्रक्रिया जारी है।

ब्रिटेन की गृह मंत्री शबाना महमूद ने मामले के बाद देश की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को ईरानी शासन से गंभीर सुरक्षा चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि ईरान से जुड़े नेटवर्क यहूदी समुदायों को निशाना बनाने तथा विदेशों में ईरानी शासन के आलोचकों को दबाने के लिए प्रॉक्सी और आपराधिक नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिटेन सरकार इससे पहले भी ईरान से जुड़े कथित गुप्त अभियानों को लेकर चिंता जताती रही है। दूसरी ओर, ईरान ब्रिटेन और पश्चिमी देशों की ओर से लगाए जाने वाले ऐसे आरोपों को खारिज करता रहा है।

मैनचेस्टर में सामने आया यह मामला ऐसे समय आया है जब ब्रिटेन में यहूदी समुदाय की सुरक्षा को लेकर पहले से ही चिंता बनी हुई है। पिछले वर्ष अक्टूबर में योम किप्पुर के दौरान मैनचेस्टर के हीटन पार्क सिनेगॉग पर हमला हुआ था। उस घटना में दो लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसियों ने यहूदी धार्मिक स्थलों और समुदाय से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। नए मामले ने एक बार फिर धार्मिक स्थलों और समुदायों को संभावित आतंकी हमलों से बचाने की चुनौती को सामने ला दिया है।

ब्रिटिश अधिकारियों के अनुसार, देश में आतंकवादी खतरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। ब्रिटेन में आतंकवाद से संबंधित खतरे के आकलन में इस्लामी चरमपंथ और चरम दक्षिणपंथी आतंकवाद के साथ-साथ यहूदी समुदाय और अन्य संवेदनशील समूहों के खिलाफ संभावित हिंसक गतिविधियों को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ऑनलाइन कट्टरपंथ, विदेशी नेटवर्क और व्यक्तिगत स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों की तैयारी जैसी चुनौतियां आतंकवाद विरोधी अभियान को और जटिल बनाती हैं।

पुलिस जांच के अनुसार, आरोपियों की गतिविधियों की निगरानी के दौरान कथित तौर पर ऐसे संकेत मिले जिनसे संभावित हमले की तैयारी का संदेह पैदा हुआ। इसके बाद काउंटर टेररिज्म अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। जांच का दायरा अब कथित तौर पर संपर्कों, वित्तीय गतिविधियों, बरामद सामग्री और संभावित विदेशी नेटवर्क तक बढ़ाया गया है। अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कथित साजिश में और कौन लोग शामिल थे तथा आरोपियों को किसी संगठन या बाहरी नेटवर्क से निर्देश मिल रहे थे या नहीं।

सलाम अहमद्यान और रहमान सालेही को 3 अक्टूबर को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को हिरासत में भेज दिया है। मामले में अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को ओल्ड बेली में निर्धारित की गई है। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपों की गंभीरता और कथित साजिश से संबंधित तथ्यों को सामने रखा गया, जबकि आगे की न्यायिक प्रक्रिया में आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच होगी। दोनों आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अभी अदालत में साबित किया जाना बाकी है।

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि मैनचेस्टर में यहूदी समुदाय से जुड़ी कथित साजिश का मामला आरएएफ फेयरफोर्ड से संबंधित एक अलग कथित साजिश से अलग है। दोनों मामलों को आपस में जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियां संबंधित मामलों की अलग-अलग जांच कर रही हैं। मामले ने ब्रिटेन में आतंकवाद के बदलते स्वरूप और संवेदनशील समुदायों की सुरक्षा को लेकर बहस फिर तेज कर दी है। विशेष रूप से धार्मिक त्योहारों और महत्वपूर्ण अवसरों के दौरान सुरक्षा एजेंसियों पर अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखने का दबाव रहता है। योम किप्पुर यहूदी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर है और ऐसे समय में कथित हमले की तैयारी का मामला सामने आने से सुरक्षा चिंताएं और बढ़ गई हैं।

फिलहाल दोनों आरोपी हिरासत में हैं और जांच जारी है। पुलिस संभावित विदेशी संपर्कों, कथित रेकी, विस्फोटक उपकरणों की तैयारी और संभावित लक्ष्यों से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। अदालत में आगे होने वाली सुनवाई में जांच से जुड़े और तथ्य सामने आने की संभावना है। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए चुनौती यह है कि आतंकवादी नेटवर्क की संभावित गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई के साथ-साथ किसी भी समुदाय विशेष के खिलाफ भय का माहौल पैदा होने से भी रोका जाए।

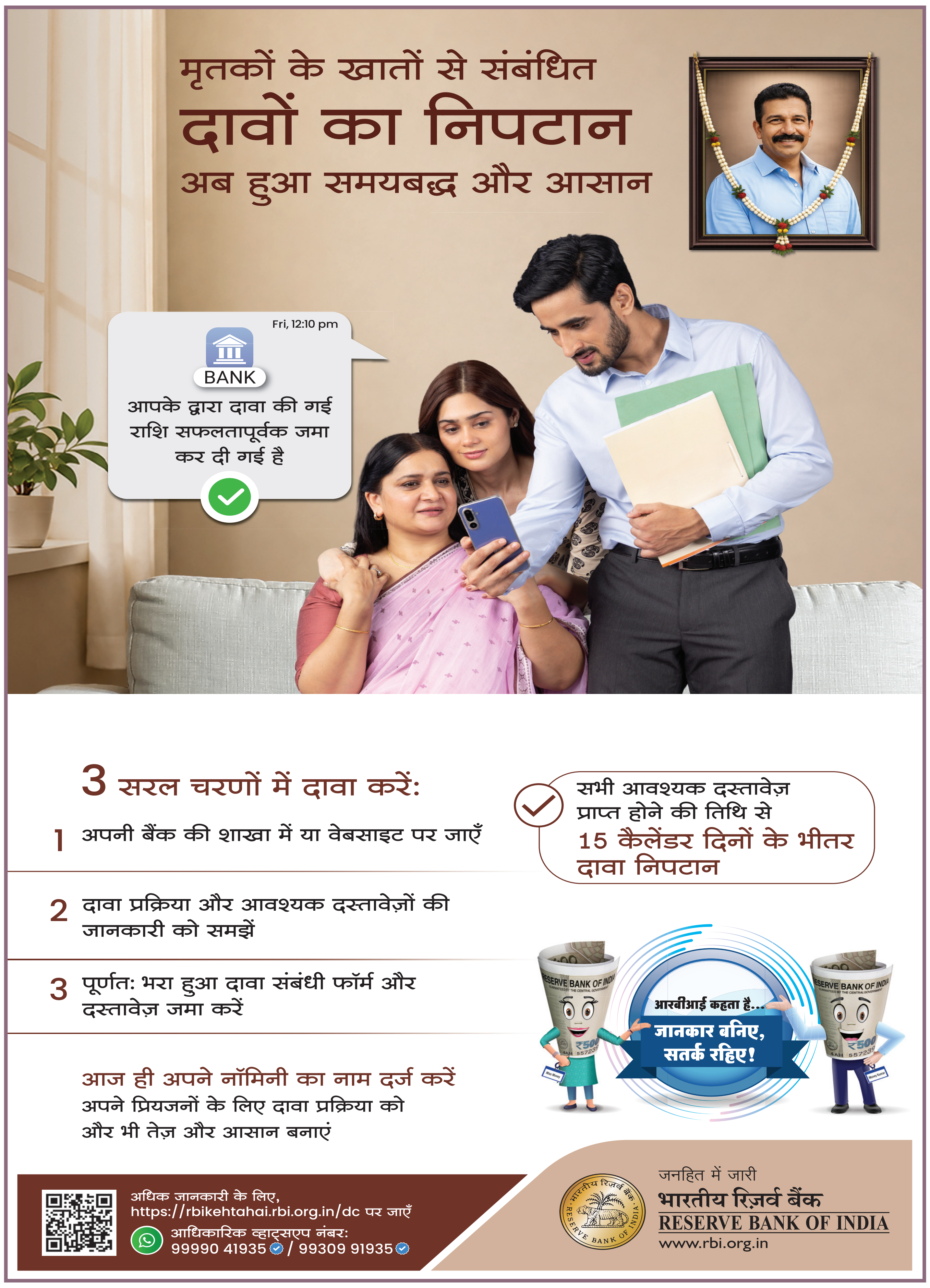

दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों पर बड़ी चोट, डेढ़ साल में 217 लाख टन कचरा साफ

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वर्षों से चुनौती बने कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने की दिशा में सरकार ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। पिछले करीब डेढ़ साल में ओखला, भलस्वा और गाजीपुर स्थित प्रमुख कूड़ा निस्तारण स्थलों से 217.17 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का निस्तारण किया जा चुका है। इस अभियान के साथ करीब 100 एकड़ जमीन को भी कचरे के ढेर से मुक्त कराया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को ओखला कूड़ा निस्तारण स्थल का दौरा कर वहां चल रहे कचरा निस्तारण और प्रसंस्करण कार्यों का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों से अभियान की प्रगति की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पुराने कचरे के निस्तारण की मौजूदा स्थिति, अब तक खाली कराई गई जमीन तथा कूड़ा प्रसंस्करण के लिए स्थापित और प्रस्तावित इकाइयों की क्षमता के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि दिल्ली में वर्षों से जमा कचरे के पहाड़ों को कम करना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन केवल पुराने कचरे को हटाना पर्याप्त नहीं होगा। रोजाना राजधानी में उत्पन्न होने वाले नए कचरे का समयबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है, ताकि साफ किए जा रहे लैंडफिल स्थल दोबारा कचरे के पहाड़ में तब्दील न हों।

दिल्ली के ओखला, भलस्वा और गाजीपुर लैंडफिल स्थल लंबे समय से शहर के कचरा प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल रहे हैं। इन स्थानों पर वर्षों से लगातार कचरा जमा होने के कारण विशाल कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए थे। इनके कारण आसपास रहने वाली आबादी को दुर्गंध, प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है। बारिश के मौसम में स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो जाती है, जबकि गर्मी के दौरान आग लगने की घटनाओं से भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में पुराने कचरे को हटाकर जमीन को खाली कराने की प्रक्रिया को राजधानी की पर्यावरणीय स्थिति सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सरकार के अनुसार, करीब 100 एकड़ जमीन को कचरे से मुक्त कराया जाना इस अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। जमीन खाली होने के बाद इसका उपयोग भविष्य की कचरा प्रबंधन व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधाओं या अन्य जरूरी शहरी कार्यों के लिए किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा कि खाली कराई गई जमीन पर दोबारा कचरा जमा न हो। इसी वजह से मुख्यमंत्री ने पुराने कचरे के निस्तारण के साथ-साथ नए कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण पर विशेष जोर दिया है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नई कचरा प्रसंस्करण इकाइयों को जल्द से जल्द पूरी क्षमता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजधानी में रोजाना बड़ी मात्रा में कचरा निकलता है और यदि उसका समय पर प्रसंस्करण नहीं किया गया तो पुराने कचरे के निस्तारण से हासिल हुई उपलब्धियां लंबे समय तक कायम नहीं रह पाएंगी। इसलिए कचरा संग्रहण से लेकर उसके पृथक्करण, प्रसंस्करण और अंतिम निस्तारण तक पूरी व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है।

सरकार की योजना केवल कचरे को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर डालने तक सीमित नहीं है। कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ उससे उपयोगी संसाधन तैयार करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। कचरे के प्रसंस्करण से उपयोगी सामग्री को अलग करने तथा ऐसे कचरे का बेहतर इस्तेमाल करने की दिशा में भी व्यवस्था विकसित की जा रही है। इससे लैंडफिल पर निर्भरता कम करने के साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले दबाव को भी घटाया जा सकता है।

कचरे के पहाड़ों को खत्म करने की चुनौती केवल प्रशासनिक अभियान से पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कचरे का स्रोत पर ही पृथक्करण, नियमित संग्रहण और प्रसंस्करण व्यवस्था को प्रभावी बनाना जरूरी है। यदि गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग एकत्र किया जाए तथा पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अलग किया जाए तो लैंडफिल तक पहुंचने वाले कचरे की मात्रा में काफी कमी लाई जा सकती है। सरकार द्वारा वैज्ञानिक प्रसंस्करण पर जोर दिए जाने के पीछे यही व्यापक उद्देश्य माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से कहा कि कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। पुराने कचरे के निस्तारण की गति बनाए रखने के साथ नई प्रसंस्करण क्षमता को भी समय पर विकसित करना होगा। उन्होंने साफ किए जा रहे क्षेत्रों की स्थिति की नियमित निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि वहां फिर से कचरे का जमाव न हो।

दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने का अभियान पर्यावरण और शहरी जीवन की गुणवत्ता से सीधे जुड़ा हुआ है। लैंडफिल स्थलों पर जमा पुराने कचरे को हटाने से जमीन का पुनः उपयोग संभव होगा और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण का दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है। साथ ही वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन व्यवस्था मजबूत होने से भविष्य में नए लैंडफिल विकसित करने की जरूरत भी कम हो सकती है।

सरकार का लक्ष्य दिल्ली में वर्षों से बने कूड़े के पहाड़ों को चरणबद्ध तरीके से खत्म कर राजधानी को स्वच्छ और बेहतर शहर के रूप में विकसित करना है। 217.17 लाख मीट्रिक टन कचरे के निस्तारण और करीब 100 एकड़ जमीन खाली कराने की उपलब्धि इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब चुनौती इस प्रगति को आगे बढ़ाने और रोजाना निकलने वाले नए कचरे का प्रभावी प्रसंस्करण सुनिश्चित करने की है।

संपादकीय

एसआईआर और पढ़ाई

देश भर में वोटर लिस्टों में संशोधन के उद्देश्य से चलाये जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी एसआईआर आज प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों से कड़ी जांच के दायरे में हैं। करोड़ों नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने के आरोप भी लगे हैं। राजनीतिक प्रतिरोध मुखर होने के बाद अब भारत के चुनाव आयोग ने राज्यों के चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उन इलाकों में छूट गए और नये वोटरों को शामिल करने के लिये विशेष अभियान चलाएं, जहां लिस्ट में सुधार का काम पूरा हो चुका है। निस्संदेह, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन का दायरा बहुत बड़ा है। देश में आजकल इसका तीसरा चरण चल रहा है। जिसके चलते छात्रों की पढ़ाई में आ रहे व्यवधान से समस्या जटिल हो गई है। देश में बड़ी संख्या में बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं। जिनके एसआईआर में लगे होने के कारण छात्रों की पढ़ाई पर खासा प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मसलन, कर्नाटक में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्र मिड-टर्म परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। वजह स्पष्ट है कि उनके शिक्षक पिछले तीन महीनों से स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के कार्य में ड्यूटी कर रहे हैं। जिसके चलते नियमित कक्षाएं नहीं चल पायी हैं। इसी तरह महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से भी ऐसी ही व्यवधान की खबरें आ रही हैं। दरअसल, शिक्षक अपना काफी समय वोटर वेरिफिकेशन, मीटिंग और आंकड़े जुटाने में लगा रहे हैं। बताते हैं कि मुंबई के एक स्कूल के 34 में से 24 शिक्षक बीएलओ की ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाना कठिन नहीं है कि छात्रों की पढ़ाई किस हद तक प्रभावित हो रही होगी। इसमें दो राय नहीं है कि पारदर्शी लोकतंत्र के लिये वोटर लिस्ट में सुधार करना निश्चित रूप से जरूरी है। मकसद यही है कि कोई योग्य वोटर न छूट जाए।

यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि देश के सरकारी स्कूल पहले से ही अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता और पर्याप्त शिक्षकों के अभाव में छात्रों के दाखिले प्रभावित हो रहे हैं। बताते हैं कि देश में करीब एक लाख स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। वहां छात्रों की पढ़ाई का स्तर क्या होगा, इस बात का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे वातावरण में सवाल यह है कि आने वाले दिनों में छात्रों की पढ़ाई को प्रभावित किए बिना एसआईआर का कार्य किया जा सकता है? निस्संदेह, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन का कार्य अपने आप में लोकतंत्र में पारदर्शिता के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक तथ्य सर्वविदित भी है कि 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम' की धारा 27 शिक्षकों को पढ़ाई-लिखाई के अलावा अन्य कामों में लगाने से रोकती है। लेकिन इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण कामों, जैसी कुछ खास स्थितियों में इसकी इजाजत दी जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इस बात पर बल दिया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के काम को शिक्षकों पर असहनीय बोझ नहीं बनने दिया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि तुरंत इस स्थिति में सुधार करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आने वाले दिनों में जब शिक्षक नियमित रूप से क्लास लेने लगेंगे तो नये सिरे से स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई को सामान्य बनाया जा सकता है। हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि पिछले महीनों में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान छात्रों की पढ़ाई का जो भी नुकसान हुआ है, उसकी अविलंब भरपाई की जानी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पढ़ाई में पैदा हुए व्यवधान से छात्रों का कोई बड़ा नुकसान न हो। दरअसल, वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता बनाये रखना और बिना रुकावट शिक्षा का अनवरत जारी रहना, दोनों ही जनता के प्रति हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। इसका एक निष्कर्ष यह भी है कि भारत को भरोसेमंद वोटर लिस्ट तैयार करने और सुचारु रूप से चल रही क्लास के बीच, किसी एक को चुनने की स्थिति में नहीं होना चाहिए। यह स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

4 साल में पहली बार एक सुर में बोले रूस और यूक्रेन, दोनों को पसंद आया मोदी का प्रस्ताव

> भारत की पहल की व्यापकता का सबसे बड़ा संकेत यही है कि यह केवल गोलाबारी रोकने तक सीमित नहीं दिखती। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, बंदरगाहों, काला सागर में व्यापार और कृषि आपूर्ति जैसे उन क्षेत्रों को जोड़ने की कोशिश है, जिनका सीधा संबंध युद्ध से बाहर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा से है।

चार साल से ज्यादा समय से जंग लड़ रहे रूस और यूक्रेन के मोर्चे भले आज भी आमने-सामने हों, लेकिन शांति के सवाल पर दोनों तरफ से निकली आवाज पहली बार एक ही दिशा में जाती दिखाई दी है। और यह दिशा दी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने भारत के प्रस्ताव को युद्ध समाप्त करने के लिए सामने आए चार प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी खुलकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस संघर्ष को खत्म करने का सवाल उठाते रहे हैं और उनके पास दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान के लिए "बहुत अच्छे विचार" हैं। देखा जाये तो युद्ध के मैदान में एक-दूसरे पर हमला कर रहे मॉस्को और कीव की तरफ से आई इन टिप्पणियों ने भारत की उस कूटनीतिक पहल को अचानक केंद्र में ला दिया है, जो अब तक बंद कमरों की बातचीत से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिखाई देने लगी है।यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार यूक्रेन की ओर से भारत की पहल को सार्वजनिक रूप से इतनी स्पष्ट मान्यता मिली है। सिबिहा के अनुसार भारत ने पहली बार इस प्रक्रिया में भूमिका निभाने की इच्छा का संकेत दिया है। यूक्रेन ऊर्जा क्षेत्र और काला सागर में युद्धविराम पर विचार करने को तैयार है, बशर्ते ऊर्जा तथा बंदरगाह ढांचे पर हमले भी रुकें। साथ ही कीव ने संपर्क रेखा पर बिना शर्त युद्धविराम के विकल्प को भी खुला बताया है।

उधर, भारत की पहल की व्यापकता का सबसे बड़ा संकेत यही है कि यह केवल गोलाबारी रोकने तक सीमित नहीं दिखती। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, बंदरगाहों, काला सागर में व्यापार और कृषि आपूर्ति जैसे उन क्षेत्रों को जोड़ने की कोशिश है, जिनका सीधा संबंध युद्ध से बाहर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा से है। वहीं तुर्किये और मिस्र की पहल मुख्यतः काला सागर तथा अनाज निर्यात से जुड़ी बताई गई है, जबकि अमेरिका की पहल ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर केंद्रित है।

यहीं पुतिन का बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि मोदी रूस के साथ अच्छे और मित्रतापूर्ण संबंध होने के बावजूद लगातार युद्ध समाप्त करने का प्रश्न उठाते हैं और दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य समाधान खोजने में उनकी गहरी रुचि है। पुतिन ने मोदी के शांतिपूर्ण तरीके से और जल्द से जल्द संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों के लिए आभार भी जताया।

देखा जाये तो मोदी की यह भूमिका अचानक पैदा नहीं हुई। वर्ष 2022 में ही उन्होंने कहा था कि "यह युद्ध का युग नहीं है।" जुलाई 2024 में रूस की यात्रा के दौरान उन्होंने साफ कहा था कि बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति वार्ता सफल नहीं हो सकती और समाधान युद्धभूमि पर नहीं निकलेगा। 31 अगस्त 2026 को बिश्केक में पुतिन से मुलाकात के दौरान भी उन्होंने "अनंत युद्ध" से "युद्ध की समाप्ति" की दिशा में बढ़ने की बात कही थी।

यहीं इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सामरिक संदेश छिपा है। रूस से भारत के गहरे संबंध हैं, जबकि यूक्रेन के साथ भी भारत ने संवाद के रास्ते खुले रखे हैं। ऐसे समय में यदि भारत रूस तक अपनी बात पहुंचा सकता है और यूक्रेन भी उसकी पहल को व्यापक प्रस्ताव मानता है, तो नई दिल्ली के पास संवाद के लिए एक ऐसा कूटनीतिक स्थान बनता है जो कई पश्चिमी शक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है।

दूसरी ओर, इसी कूटनीतिक हलचल के बीच रूस ने अपनी सैन्य शक्ति का भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। दो अक्टूबर को पुतिन ने यूराल क्षेत्र में चल रहे सेंटर-2026 सैन्य अभ्यास के अंतिम चरण का निरीक्षण किया। रूस के अनुसार इस अभ्यास में लगभग 47 हजार सैनिक, 11 प्रशिक्षण क्षेत्र और कैस्पियन सागर शामिल रहे। अंतिम चरण में करीब छह हजार सैनिक उतरे। चीन, बेलारूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया और पाकिस्तान सहित कई देशों की सेनाएं इसमें शामिल रहीं तथा 55 देशों के प्रतिनिधियों ने अभ्यास देखा।

इस अभ्यास में रूस ने करीब 700 सैन्य उपकरणों, 600 से अधिक मानवरहित विमानों और 60 से अधिक रोबोटिक प्रणालियों का इस्तेमाल दिखाया। पुतिन ने नए जेट-चालित जेरान मानवरहित विमानों का भी निरीक्षण किया, जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में कर चुका है। इसका अर्थ साफ है कि मास्को युद्ध से मिले अनुभव को अगली पीढ़ी की युद्धक क्षमता में बदल रहा है। इसलिए तस्वीर बेहद दिलचस्प है। एक तरफ रूस युद्ध के मैदान में अपनी सैन्य क्षमता, मानवरहित युद्ध प्रणाली और दूर तक मार करने वाली तकनीक का प्रदर्शन कर रहा है; दूसरी तरफ उसी रूस के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के युद्ध समाप्त करने वाले विचारों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा कर रहे हैं। यही भारत की कूटनीति की असली परीक्षा और संभावित ताकत दोनों है।

लेकिन रास्ता आसान नहीं है। यूक्रेन में रूसी हमले जारी हैं, ऊर्जा ढांचा लगातार निशाने पर है और काला सागर में सुरक्षा तथा अनाज आपूर्ति का संकट बना हुआ है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार रूस और यूक्रेन दोनों एक-दूसरे के ऊर्जा तथा ईंधन ढांचे पर हमले कर रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत की चुनौती केवल प्रस्ताव देने की नहीं, बल्कि प्रस्ताव को युद्धभूमि से वार्ताकक्ष तक पहुंचाने की है। यदि नई दिल्ली रूस और यूक्रेन दोनों से संवाद कायम रखते हुए ऊर्जा, कृषि, काला सागर और अंततः व्यापक युद्धविराम को एक ही ढांचे में जोड़ पाती है, तो यह केवल एक युद्ध को रोकने की कोशिश नहीं होगी, यह बदलती विश्व व्यवस्था में भारत की बढ़ती कूटनीतिक भूमिका का बड़ा प्रमाण बन सकता है। फिलहाल इतना जरूर स्पष्ट है कि मोदी की शांति पहल को अब केवल भारतीय दावा नहीं कहा जा सकता; यूक्रेन ने उसे व्यापक प्रस्ताव बताया है और पुतिन ने स्वयं उसके पीछे मोदी की लगातार कोशिशों को स्वीकार किया है।

प्रेरणा

जब अंतरात्मा ने सुनाया फैसला

दिल्ली की एक अदालत में उस दिन सामान्य दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक भीड़ थी। अदालत कक्ष लोगों से खचाखच भरा हुआ था। न्यायाधीश के सामने एक मामले की सुनवाई चल रही थी। वातावरण में गंभीरता थी और सभी की निगाहें न्यायाधीश तथा अभियुक्त पर टिकी हुई थीं। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश की किसी व्यवस्था या निर्णय से अभियुक्त इस कदर क्षुब्ध हो गया कि उसने अपना आपा खो दिया। क्रोध में उसने पैर से चप्पल उतारी और उसे पूरी ताकत से न्यायाधीश की ओर उछाल दिया। चप्पल जाकर न्यायाधीश के पास गिरी और कुछ क्षणों के लिए पूरी अदालत में जैसे समय ठहर गया।

अभी कुछ क्षण पहले तक जहां कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, वहां अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। अदालत में मौजूद लोग स्तब्ध थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक अभियुक्त न्याय की सर्वोच्च गरिमा के प्रतीक न्यायाधीश के प्रति इस प्रकार का व्यवहार कर सकता है। पुलिस अधिकारियों और अदालत में तैनात सिपाहियों के चेहरे पर भी गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। कुछ पुलिसकर्मी तुरंत अभियुक्त की ओर बढ़े। उनके कदमों में आक्रोश था और स्वाभाविक रूप से वे अभियुक्त को उसके दुस्साहस की सजा देना चाहते थे।

लेकिन तभी न्यायाधीश ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि अभियुक्त को कुछ न कहा जाए। उसे पीटा न जाए और उसके साथ किसी प्रकार की कठोरता न बरती जाए। न्यायाधीश का कहना था कि उसने जो किया है, उसका एहसास उसे स्वयं होगा। बाहरी दंड से कहीं अधिक प्रभावशाली वह दंड होता है, जो मनुष्य को उसकी अपनी अंतरात्मा देती है। आत्म-ग्लानि और पश्चाताप मनुष्य को भीतर से झकझोर सकते हैं और कभी-कभी वही उसके जीवन का सबसे बड़ा दंड बन जाते हैं।

न्यायाधीश के आदेश के बाद पुलिसकर्मियों के बढ़ते कदम रुक गए। अदालत का वातावरण फिर शांत हो गया, लेकिन अभियुक्त के भीतर एक भयंकर तूफान उठ चुका था। कुछ समय पहले तक जिस क्रोध ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था, अब वही क्रोध धीरे-धीरे शर्म और ग्लानि में बदलने लगा। उसे अपने किए का एहसास होने लगा। उसने जिस व्यक्ति की ओर चप्पल उछाली थी, वह केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि उस पद का प्रतिनिधि था जिसके सामने न्याय पाने के लिए लोग विश्वास के साथ आते हैं।

सुनवाई समाप्त हुई। पुलिसकर्मी अभियुक्त को अदालत से बाहर ले जाने के लिए उसके पास पहुंचे। एक सिपाही ने उसका हाथ पकड़ लिया। शायद अभियुक्त अभी भी मानसिक उथल-पुथल में था। उसने गुस्से में सिपाही का हाथ झटक दिया। अदालत में मौजूद लोगों को लगा कि उसके भीतर अभी भी क्रोध बाकी है। लेकिन अगले ही क्षण जो हुआ, उसने वहां मौजूद सभी लोगों को भीतर तक हिला दिया।

अभियुक्त अचानक न्यायाधीश के सामने लगी लकड़ी की रेलिंग के पास गया और अपना सिर उस पर पटकने लगा। उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था, बल्कि गहरी पीड़ा और पश्चाताप था। वह स्वयं को अपने किए के लिए दोषी मान चुका था। उसकी आंखों और व्यवहार से स्पष्ट था कि उसे समझ आ गया था कि क्षणिक आवेश में उसने कितनी बड़ी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। वह किसी दूसरे के दंड से नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की अदालत से जूझ रहा था। उस समय अदालत में मौजूद लोगों की भावनाएं भी बदल गईं। कुछ देर पहले जो लोग उसे कठोर दंड दिए जाने की मांग कर रहे थे, वे अब मौन खड़े थे। उन्हें समझ में आ रहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी अदालत उसके भीतर ही होती है। कानून बाहरी अपराध के लिए दंड दे सकता है, लेकिन आत्मग्लानि वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से बदलने की क्षमता रखती है।

न्यायाधीश के चेहरे पर भी संतोष की झलक दिखाई दी। उन्होंने अभियुक्त को अपमानित नहीं किया, न ही उसके क्रोध का जवाब क्रोध से दिया। उन्होंने उसे स्वयं अपने व्यवहार का मूल्यांकन करने का अवसर दिया। शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। न्याय केवल अपराधी को दंडित करना नहीं है। न्याय का एक उद्देश्य यह भी है कि व्यक्ति अपने अपराध को समझे, अपनी गलती स्वीकार करे और भविष्य में उसे दोहराने से बचे।

मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी भूल का एहसास होना उसके चरित्र की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। गलती करने के बाद यदि मनुष्य उसे सही ठहराने लगे तो उसका पतन शुरू हो जाता है। इसके विपरीत यदि वह अपनी गलती स्वीकार कर ले, उसके लिए सच्चे मन से पश्चाताप करे और स्वयं को सुधारने का प्रयास करे तो वही गलती उसके जीवन में परिवर्तन का कारण बन सकती है।

इस घटना का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर अपराध का दंड केवल अदालत नहीं देती। कई बार अंतरात्मा की आवाज कानून से भी अधिक कठोर होती है। बाहरी दंड कुछ समय के लिए पीड़ा दे सकता है, लेकिन आत्मग्लानि मनुष्य को तब तक चैन नहीं लेने देती, जब तक वह अपने किए को समझ न ले। यही कारण है कि सच्चा पश्चाताप व्यक्ति को भीतर से बदल सकता है।

अदालत में उस दिन कानून की एक अलग तस्वीर दिखाई दी। न्यायाधीश ने केवल कानून की कुर्सी पर बैठकर फैसला नहीं सुनाया, बल्कि मनुष्य की मनुष्यता पर विश्वास करते हुए अभियुक्त को अपनी अंतरात्मा के सामने खड़ा होने दिया। अंततः फैसला किसी दस्तावेज में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के भीतर लिखा गया। उसे किसी सिपाही की लाठी ने नहीं, बल्कि उसके अपने विवेक ने दंड दिया। यही पश्चाताप का सबसे बड़ा दंड था और शायद सुधार की पहली सीढ़ी भी।

मच्छर, हाथी, घोड़ा और बिच्छू Gujarat के इन अजीब Surnames से जुड़ी कहानी सुनकर चौंक जाएंगे!

फ्लाईदुबई की एक उड़ान में संकट टालने वाले कप्तान स्मित मच्छर का नाम सामने आया तो उनकी बहादुरी के साथ उनके अनोखे उपनाम ने भी लोगों का ध्यान खींचा। 'मच्छर' नाम सुनकर भले ही पहले उड़ने वाले कीट की तस्वीर सामने आए, लेकिन यहां बात एक ऐसे पायलट की है, जिसने 9/11 जैसे आतंकी हमले को घटित होने से रोका और सभी विमान यात्रियों की जान बचाई। स्मित मच्छर नाम ने गुजरात के उन अनोखे उपनामों की कहानी भी सामने ला दी, जिनमें पशु-पक्षियों और कीट-पतंगों के नाम पीढ़ियों से लोगों की पहचान बने हुए हैं।हम आपको बता दें कि गुजराती समाज में विशेषकर कुछ नागर ब्राह्मण, ब्रह्मक्षत्रिय और लोहाना समुदायों में पशु-पक्षियों और कीट-पतंगों से जुड़े कई उपनाम मिलते हैं। इनमें घोड़ा, मांकड़ यानी खटमल, मांकड़ी यानी बड़ी चींटी, पोपट यानी तोता, विंछी यानी बिच्छू, शियाल यानी सियार, तीतर और हाथी जैसे उपनाम शामिल हैं। यानी एक ही सामाजिक संसार में कहीं मच्छर भनभना रहा है, कहीं बिच्छू डंक मार रहा है, कहीं घोड़ा दौड़ रहा है और कहीं हाथी चिंघाड़ रहा है!

इस कहानी में कैप्टन मनोज हाथी का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। एयर इंडिया में संचालन विभाग के पूर्व निदेशक रहे कैप्टन हाथी का उपनाम सचमुच 'हाथी' है। जब उन्होंने बोइंग 747 जैसे विशाल जंबो विमान को उड़ाने के लिए प्रशिक्षण लिया, तो उनके साथियों को मजाक करने का एक और मौका मिल गया। कैप्टन हाथी ने मीडिया को बताया कि एयर इंडिया में उनके समय कप्तान वाघ और पारसी इनफ्लाइट पर्यवेक्षक होमी घोड़ा भी थे। यानी विमानन जगत में उनके आसपास ही पूरा 'जंगल' बसा हुआ था।

विदेश में भी कैप्टन हाथी के नाम ने खूब ध्यान खींचा, लेकिन वहां इसे याद रखना लोगों के लिए आसान था। ब्रिटेन में कई लोग उनके नाम को 'द जंगल बुक' के मशहूर किरदार कर्नल हाथी से जोड़ लेते थे। भारत में लोग अक्सर उनसे मजाक में पूछते थे कि जब उपनाम हाथी है तो इतने दुबले क्यों हैं? अब वजन थोड़ा बढ़ा तो मजाक भी बदल गया। लोग कहने लगे कि अब कैप्टन हाथी अपने नाम के साथ पूरी तरह न्याय कर रहे हैं।

इसके अलावा, गुजरात के जूनागढ़ के नागर समुदाय से जुड़े फिल्मकार अभिलाष घोड़ा भी अपने उपनाम को गर्व से धारण करते हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उनका कहना है कि गुजरात से बाहर यह नाम अक्सर लोगों का ध्यान खींचता है, लेकिन उनके परिवार ने इसे पीढ़ियों से सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपनाया है। हालांकि परिवार के कई लोगों को भी यह निश्चित रूप से पता नहीं कि इस उपनाम की मूल उत्पत्ति क्या रही होगी।

वहीं 'मच्छर' उपनाम का संबंध गुजरात के ब्रह्मक्षत्रिय समुदाय से बताया जाता है। वाधवान स्थित समुदाय संस्था के सचिव राजू दुबल के अनुसार, सुरेंद्रनगर सहित गुजरात के कुछ इलाकों में यह उपनाम विशेष रूप से देखने को मिलता है। अहमदाबाद की भारती विंछी भी ब्रह्मक्षत्रिय समुदाय से आती हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे उपनाम समुदाय में संख्या की दृष्टि से कम हैं। परिवार में बुजुर्गों से मिली जानकारी के अनुसार उनके पूर्वज कीटों के काटने, खासकर बिच्छू के डंक का उपचार करने में दक्ष माने जाते थे। इसी कारण बिच्छू से जुड़ा नाम समुदाय की पहचान का हिस्सा बन गया। इस परंपरा में केवल पशु-पक्षी और कीट ही नहीं, बल्कि भूत और जोगी जैसे उपनाम भी मिलते हैं।

इस पूरे मामले पर समाजशास्त्री गौरांग जानी का कहना है कि गुजराती उपनामों के इतिहास पर विनोदिनी नीलकंठ की 1942 में प्रकाशित पुस्तक 'गुजराती अटकाओं नो इतिहास' अब भी महत्वपूर्ण विद्वतापूर्ण स्रोत मानी जाती है। उनके अनुसार, ऐसे उपनामों को संभावित रूप से 'टोटेम' परंपराओं से जोड़ा जा सकता है। अर्थात किसी समूह का किसी विशेष पशु के प्रति सम्मान, उससे जुड़ाव या उसके सकारात्मक गुणों को अपनाने की सामाजिक परंपरा रही थी। गौरांग जानी के मुताबिक सौराष्ट्र में ऐसे उपनामों की अधिकता का कारण बड़े जातीय ढांचे से ज्यादा वहां के करीबी और आपस में जुड़े समुदायों की मजबूत सामाजिक संरचना हो सकती है।

बहरहाल, अगली बार जब किसी खबर में कैप्टन मच्छर, कैप्टन हाथी या कोई घोड़ा दिखाई दे, तो नाम पर मुस्कुराने से पहले कहानी जरूर समझिए। क्योंकि गुजरात के इन उपनामों के पीछे केवल मजेदार शब्द नहीं, बल्कि समुदाय, परंपरा, पेशे, लोकविश्वास और सदियों पुरानी सामाजिक स्मृतियों की पूरी कहानी छिपी हो सकती है। और हां, मच्छर का विमान उड़ाना जितना असामान्य सुनाई देता है, हाथी का जंबो जेट उड़ाना उससे कहीं ज्यादा शानदार संयोग है!

अभियान

कर्ण को स्वर्ग में भोजन की जगह मिला सोना, पितरों की एक भूल ने सिखाया दान का असली अर्थ

भारतीय सनातन परंपरा में पितृपक्ष को पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का विशेष समय माना जाता है। वर्ष में आने वाले इन दिनों में परिवार अपने दिवंगत सदस्यों को स्मरण करता है और उनकी आत्मिक शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान तथा दान-पुण्य करता है। यह परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं मानी जाती, बल्कि इसके पीछे परिवार की जड़ों को याद रखने और पिछली पीढ़ियों के प्रति सम्मान प्रकट करने की भावना भी जुड़ी है। पितृपक्ष आते ही घरों में पूर्वजों की चर्चा होने लगती है। लोग उनकी स्मृति में भोजन बनाते हैं, जल अर्पित करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करते हैं।

पितृपक्ष की परंपरा के साथ कई धार्मिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। इनमें महाभारत के महान योद्धा और दानवीर कर्ण की कथा सबसे अधिक चर्चित मानी जाती है। कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा गुण उनकी दानशीलता थी। लोकमान्यता है कि उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। धन, स्वर्ण और बहुमूल्य वस्तुओं का दान करने के कारण उन्हें दानवीर कहा गया। लेकिन यही कर्ण जब मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचे तो उनके सामने एक ऐसी परिस्थिति आई, जिसने उन्हें अपने जीवन की एक भूल का एहसास कराया। उन्हें भोजन के लिए अन्न के बजाय सोना दिया गया। कर्ण के लिए यह किसी रहस्य से कम नहीं था।

कथा के अनुसार कर्ण ने स्वर्ग में जब भोजन मांगा तो उन्हें खाने के लिए सोना दिया गया। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि आखिर उन्हें अन्न के स्थान पर सोना क्यों दिया जा रहा है। तब उन्हें बताया गया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने धन, स्वर्ण और आभूषणों का तो खूब दान किया, लेकिन अपने पितरों के लिए अन्न और जल का दान नहीं किया। उन्होंने पूर्वजों का विधिपूर्वक तर्पण भी नहीं किया था। इसलिए उन्हें स्वर्ग में वही प्राप्त हो रहा था, जिसे उन्होंने अपने जीवन में सबसे अधिक दान किया था।

यह बात कर्ण के लिए आत्ममंथन का कारण बनी। वह महान दानी थे, लेकिन उन्हें यह समझ में आया कि दान की महत्ता केवल वस्तु के मूल्य से निर्धारित नहीं होती। किसके लिए, किस भावना से और किस आवश्यकता को ध्यान में रखकर दान किया गया है, इसका भी अपना महत्व है। कर्ण ने जीवन में असंख्य लोगों को धन दिया था, लेकिन अपने पितरों के निमित्त अन्न-जल अर्पित करने की परंपरा पूरी नहीं की थी। लोककथा इसी प्रसंग के माध्यम से यह संदेश देती है कि मनुष्य को अपने सभी दायित्वों का ध्यान रखना चाहिए।

कर्ण ने देवताओं से अपनी भूल सुधारने का अवसर मांगा। उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें कुछ समय के लिए धरती पर लौटने दिया जाए, ताकि वह अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान कर सकें। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और लोकमान्यता के अनुसार उन्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस आने का अवसर मिला। धरती पर लौटकर कर्ण ने पितरों के निमित्त अन्न और जल अर्पित किया। उन्होंने जरूरतमंदों को भोजन कराया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-पुण्य किया। कहा जाता है कि इसी प्रसंग से पितृपक्ष की परंपरा को जोड़कर देखा जाता है और कई स्थानों पर इसे करणागत नाम से भी जाना जाता है।

कर्ण की यह कथा धार्मिक ग्रंथों की विभिन्न परंपराओं में अलग-अलग रूपों में कही जाती है, लेकिन इसका मूल संदेश एक ही है—पूर्वजों को भूलना नहीं चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में चाहे कितनी भी सफलता हासिल कर ले, उसकी जड़ें उसके परिवार और पूर्वजों से जुड़ी होती हैं। वर्तमान पीढ़ी के अस्तित्व के पीछे पिछली पीढ़ियों का योगदान होता है। इसलिए उन्हें याद करना और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना कर्तव्य के रूप में देखा गया है।

पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने की विधि भी विशेष मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस तिथि को किसी व्यक्ति का निधन हुआ हो, पितृपक्ष में उसी तिथि पर उसका श्राद्ध किया जाता है। इस अवसर पर जल, तिल और अन्य सामग्री से तर्पण किया जाता है। कई परिवार चावल, जौ, तिल, घी और शहद आदि से पिंड तैयार करके पितरों को अर्पित करते हैं। विधि-विधान क्षेत्र, परिवार और परंपरा के अनुसार अलग हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धा और स्मरण का भाव सभी जगह प्रमुख रहता है।

श्राद्ध के अवसर पर भोजन कराने और दान देने की भी परंपरा है। कई परिवार ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, जबकि अनेक लोग साधु-संतों और जरूरतमंदों को भोजन तथा वस्त्र आदि दान करते हैं। इसके पीछे यह भावना रहती है कि पितरों के नाम पर किया गया पुण्य कार्य उनके प्रति श्रद्धा का प्रतीक बने। भोजन को विशेष महत्व इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि अन्न को जीवन का आधार माना गया है। कर्ण की कथा में भी अन्न और जल को लेकर जो संदेश दिया गया है, वह इसी भावना से जुड़ा हुआ है।

पितृपक्ष में पशु-पक्षियों को भोजन कराने की परंपरा भी कई परिवारों में प्रचलित है। कौए, गाय, कुत्ते और चींटियों के लिए भोजन निकालने की मान्यता है। कुछ स्थानों पर पक्षियों को दाना-पानी भी दिया जाता है। धार्मिक दृष्टि से इन परंपराओं के अलग-अलग अर्थ बताए जाते हैं, जबकि सामाजिक दृष्टि से देखें तो यह जीव-जंतुओं के प्रति करुणा और सह-अस्तित्व की भावना को बढ़ाने का माध्यम भी बन सकता है।

पितृपक्ष के दौरान देश के अनेक तीर्थस्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देती है। गया में पिंडदान की विशेष परंपरा है। इसके अलावा वाराणसी, प्रयागराज और हरिद्वार सहित कई धार्मिक स्थलों पर लोग पितरों का तर्पण करने पहुंचते हैं। पवित्र नदियों के किनारे लोग विधि-विधान से जल अर्पित करते हैं और पूर्वजों की स्मृति में पूजा करते हैं। कई परिवारों में यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और परिवार के बुजुर्ग नई पीढ़ी को इससे जुड़ी विधियां और मान्यताएं बताते हैं।

पितृपक्ष के दिनों को लेकर यह मान्यता भी है कि इस अवधि में विवाह, गृहप्रवेश और अन्य बड़े मांगलिक कार्यों को टाल दिया जाता है। लोग इन दिनों को अपने पितरों के स्मरण और धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित करते हैं। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में इससे जुड़ी मान्यताएं अलग-अलग हो सकती हैं। कहीं पूरे पक्ष में विशेष नियमों का पालन किया जाता है तो कहीं परिवार अपनी स्थानीय परंपराओं के अनुसार श्राद्ध और तर्पण करता है।

कर्ण की कथा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसमें दान की भावना को केवल संपत्ति देने तक सीमित नहीं किया गया। किसी व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार सहायता देना भी दान की भावना का हिस्सा है। किसी भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना, गरीब को वस्त्र देना या असहाय व्यक्ति की मदद करना भी सेवा का रूप माना जाता है। इस दृष्टि से पितृपक्ष में किया जाने वाला दान धार्मिक परंपरा के साथ सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश भी देता है।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार छोटे हो रहे हैं और कई लोग अपने गांव, पुराने घर तथा परिवार की पिछली पीढ़ियों से दूर रहने लगे हैं। ऐसे समय में पितृपक्ष लोगों को अपने पारिवारिक इतिहास से जोड़ने का अवसर देता है। इस दौरान बुजुर्ग अपने बच्चों और पोते-पोतियों को परिवार के दिवंगत सदस्यों की कहानियां सुनाते हैं। इससे नई पीढ़ी को यह जानने का अवसर मिलता है कि उनके परिवार की पिछली पीढ़ियों ने किस तरह जीवन बिताया, किन कठिनाइयों का सामना किया और कौन से संस्कार आगे बढ़ाए। कर्ण की कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मनुष्य को अपने जीवन के हर दायित्व के प्रति सजग रहना चाहिए। कर्ण महान दानी थे, लेकिन लोककथा में उनकी एक भूल को सामने रखकर यह बताया गया है कि केवल धन का दान ही पर्याप्त नहीं है। परिवार, समाज और पूर्वजों के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन भी आवश्यक है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M), 9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में 'बेस्ट आत्मा फार्मर्स अवॉर्ड' वितरण समारोह आयोजित

‘पहला सुख निरोगी काया’ : रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से बचने के लिए प्राकृतिक खेती अपनाना समय की मांग : राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत

विकास का अर्थ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में गुणात्मक बदलाव लाना भी है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत

- प्राकृतिक कृषि का दायरा दोगुना करने के लिए ‘एक किसान, एक नए किसान को जोड़े’
- प्राकृतिक कृषि उत्पाद के बिक्री केंद्र ग्राहकों के विश्वास के केंद्र बनें

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- गुजरात प्राकृतिक कृषि, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण संरक्षण के समन्वय से अन्नदाता के सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ा
- मिट्टी की सेहत और मानव स्वास्थ्य एक-दूसरे से जुड़े होने के कारण प्राकृतिक खेती को जनआंदोलन बनाने का मुख्यमंत्री का अनुरोध

कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार का ‘ब्रांड एंबेसडर’ बताते हुए, पांच अन्य किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ने का संकल्प लेने का आह्वान किया

93 प्रगतिशील किसानों को ‘श्रेष्ठ आत्मा फार्मर्स अवॉर्ड’ से नवाजा गया

100 नए प्राकृतिक कृषि बिक्री केंद्रों का लोकार्पण

आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए खेती निदेशक कार्यालय और एसएसी-इसरो के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर

नवनियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित, कृषि निदेशालय की विभिन्न पुस्तकों का विमोचन

गांधीनगर : राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में शनिवार को गांधीनगर में गुजरात के 93 प्रगतिशील किसानों को राज्य एवं जिला स्तरीय ‘श्रेष्ठ आत्मा फार्मर्स अवॉर्ड’ दिए गए। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी विशेष रूप से मौजूद रहे।

इस मौके पर प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को उचित प्लेटफॉर्म प्रदान कर ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में लगभग 100 प्राकृतिक कृषि उत्पाद बिक्री केंद्रों का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही राज्य में प्राकृतिक कृषि उत्पादों के कुल बिक्री केंद्रों की संख्या बढ़कर 1200 हो गई है।

समारोह में खेती में आधुनिक सैटेलाइट और जियो-स्पेशियल टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि निदेशालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी-सैक) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि विस्तार सेवाओं को और अधिक तेज एवं प्रभावी बनाने के लिए सहायक कृषि निदेशक (वर्ग-2) के रूप में चयनित 14 नवनियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने कहा कि ‘पहला सुख, निरोगी काया’ – शरीर का स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। रासायनिक उर्वरकों

और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से भूमि, पानी और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने तथा मानव स्वास्थ्य एवं आने वाली पीढ़ी के भविष्य की रक्षा के लिए प्राकृतिक कृषि का दायरा बढ़ाना आवश्यक है।

राज्यपाल ने डेनमार्क की मिसाल देते हुए कहा कि वहां यूरिया-डीएपी पर कोई सब्सिडी नहीं है। वहां गाय के गोबर और मूत्र से गोबर गैस और जैविक खाद बनाकर भूमि में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को 2 फीसदी बनाए रखा गया है।

प्राकृतिक कृषि उत्पादों के बिक्री केंद्रों के लोकार्पण का स्वागत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि राज्य में आज 100 से अधिक बिक्री केंद्र शुरू हो चुके हैं। ये केंद्र केवल बिक्री के स्थल नहीं, बल्कि ग्राहकों के विश्वास के केंद्र भी बनने चाहिए। यहां शुद्ध प्राकृतिक कृषि उत्पादों की ही बिक्री हो तथा उनकी गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी किसानों एवं संचालकों की है। उन्होंने इन केंद्रों के बारे में जागरूकता फैलाकर अधिक से अधिक नागरिकों तक इसकी जानकारी पहुंचाने का अनुरोध किया।

राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती करने वाले प्रत्येक किसान से कम से कम एक नए किसान को इस अभियान से जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने तथा देसी गाय के पालन के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। इस अवसर पर राज्यपाल ने पुरस्कृति किसानों को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि उनका कार्य दूसरे किसानों के लिए प्रेरणादायी बनेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 25 वर्षों की राष्ट्रसेवा और जनसेवा में सुशासन, विकास, टेक्नोलॉजी और जनकल्याण को केंद्र में रखकर विभिन्न पहलें की गई हैं। उन्होंने कहा कि विकास का अर्थ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में गुणात्मक बदलाव लाना भी है।

मुख्यमंत्री ने हा कि 21वीं सदी के भारत के विकास में ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान’ के साथ ‘जय अनुसंधान’ का जो नया मंत्र दिया है, वह देश की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, वैज्ञानिक प्रगति और अनुसंधान को एक साथ जोड़ता है।

उन्होंने कहा कि आज गुजरात प्राकृतिक खेती, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण संरक्षण के समन्वय से अन्नदाता के सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी और अनुसंधान के उपयोग से किसानों की आय, उत्पादन क्षमता और संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए नए अवसर बन रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक कृषि को अधिक व्यापक बनाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि मिट्टी की सेहत और मानव स्वास्थ्य एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। रासायनिक इनपुट के उचित एवं संतुलित उपयोग, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने और टिकाऊ खेती पद्धतियों के बारे में किसानों में जागरूकता बढ़ाना समय की मांग है।

उन्होंने कहा कि राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत के मार्गदर्शन में, गुजरात में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय कार्य हो रहा है। यदि प्राकृतिक खेती करने वाले किसान अपने खेतों को दूसरे किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बनाएं और व्यावहारिक नतीजे दिखाएं, तो और अधिक किसान इस पद्धति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि प्राकृतिक खेती के साथ जल संचय और पानी के विवेकपूर्ण उपयोग को भी प्राथमिकता देना जरूरी है। बारिश के पानी का अधिकतम संग्रह, भूमिगत जल के रिचार्ज और पानी के कुशल उपयोग के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा के उत्सव के तहत आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में ‘सेवा’ को केंद्र स्थान पर रखा गया है। स्वच्छता बनाए रखना, पानी बचाना, बिजली का अनावश्यक इस्तेमाल कम करना, ईंधन की बचत करना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना भी समाज सेवा के ही रूप हैं। उन्होंने लोगों से इस प्रकार के छोटे लेकिन प्रभावी संकल्पों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का भी अनुरोध किया।

उन्होंने किसानों से यह भी कहा कि यदि उन्हें प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन या उपज की बिक्री में कोई कठिनाई हो, तो वे इसे राज्य सरकार के ध्यान में लाएं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बेस्ट फार्मर का अवॉर्ड प्राप्त करने वाले किसानों तथा राज्य की कृषि सेवा से जुड़े अधिकारियों को बधाई दी।

कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मिशन और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्राकृतिक कृषि अब एक बड़ा अभियान बन चुकी है। पढ़े-लिखे युवा भी अब प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ रहे हैं। सरकार इस बात को लेकर लगातार प्रयासरत है कि किसानों को उनके उत्पादों की उचित मार्केटिंग और सर्टिफिकेशन मिले। कृषि मंत्री ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार का ‘ब्रांड एंबेसडर’ बताते हुए पांच अन्य किसानों को इस क्षेत्र से जोड़ने का संक्प लेने का आह्वान किया।

उत्तराखंड के बाद गुजरात देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है, जिसके समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। आदिवासी क्षेत्र की परंपरागत व्यवस्थाओं और संस्कृति को बनाए रखते हुए समग्र राज्य में एक समान कानून लाने के इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए कृषि मंत्री ने गुजरात की जनता की ओर से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का आभार व्यक्त किया और उन्हें बधाई दी।

इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने कृषि विभाग के ‘एनुअल एक्शन प्लान 2026-27’, ‘खेतीवाड़ी खातानी सहायलक्षी योजनाओ’ तथा ‘बागायत खातानी सहायलक्षी योजना’ पुस्तकों का विमोचन भी किया। समारोह की शुरुआत में कृषि विभाग के प्रधान सचिव श्री आर.सी. मीणा ने स्वागत भाषण में पूरे कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा दी।

कार्यक्रम में गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक श्री विजय खराड़ी सहित कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा, पूरे राज्य से मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण तथा स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों सहित लगभग 50,000 किसान वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में गुजरात सरकार का महत्वपूर्ण कदम

गुजरात को ‘ग्लोबल कैपेबिलिटी हब’ बनाने के लिए डिजिटल इंसेंटिव का नया रोडमैप : आवेदन से भुगतान तक की प्रक्रिया अब एक ही पोर्टल पर

जीसीसी पॉलिसी 2025-30 के क्रियान्वयन के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस 1.0 जारी

नए जीसीसी की स्थापना और मौजूदा सेंटर के विस्तार को प्रोत्साहन

कैपेक्स, ओपेक्स और स्पेशल इंसेंटिव के लिए पात्रता तथा समयसीमा निर्धारित

देरी से किए गए क्लेम पर प्रो-राटा के आधार पर इंसेंटिव की गणना

जीसीसी की पहचान से निवेश और कर्मचारियों की जाँच तक की प्रक्रिया दस्तावेज आधारित

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गुजरात में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के विकास को नया वेग देने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गुजरात ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) पॉलिसी 2025-30 के असरकारक अमल के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस 1.0 जारी की गई हैं। इस मार्गदर्शिका द्वारा जीसीसी की पहचान, पात्रता, नए सेंटर की स्थापना, मौजूदा सेंटर के विस्तार और विभिन्न प्रोत्साहक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए स्पष्ट ढाँचा निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया के नेतृत्व में जारी की गई इस मार्गदर्शिका की विशेषता यह है कि इंसेंटिव के लिए आवेदन से लेकर क्लेम की जाँच और भुगतान तक की कार्रवाई एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी। डायरेक्टोरेट ऑफ आईसीटी एंड ई-गवर्नेंस द्वारा विकसित इंटीग्रेटेड इंसेंटिव मैनेजमेंट पोर्टल द्वारा इंसेंटिव का आवेदन, क्लेम प्रोसेसिंग, भुगतान के अलावा स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा। जीसीसी पॉलिसी संबंधित जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

पात्रता निर्धारित करने के लिए स्पष्ट मापदंड

जीसीसी के लिए इंसेंटिव की गणना कब से शुरू होगी, यह निर्धारित करने के लिए मंथ ऑफ एलिजिबिलिटी का प्रावधान किया गया है। कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने की तारीख, इन-प्रिंसिपल अप्रूवल अथवा एलिजिबल एम्प्लॉयी काउंट हासिल होने की तारीख; इन तीनों में से जो तारीख सबसे पीछे की होगी, उसे पात्रता का प्रारंभिक महीना माना जाएगा। इसी समय से इंसेंटिव के भुगतान की गणना शुरू होगी।

जीसीसी की पहचान के लिए पेरेंट अथवा ग्रुप कंपनी के साथ संबंध दर्शाने वाला बोर्ड रिजोल्यूशन, सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एसएलए), ओनरशिप स्ट्रक्चर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर), जीएसटी सर्टिफिकेट और आवश्यक हो वहाँ सीए द्वारा प्रमाणित निवेश की विवरण प्रस्तुत करनी होगी। कमर्शियल ऑपरेशन पॉलिसी पीरियड के दौरान शुरू हुआ होना अनिवार्य है।

नए जीसीसी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉरपोरेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, गुजरात में संपत्ति के किराये या खरीद के दस्तावेज, जीसीसी स्थापित करने के लिए बोर्ड रिजोल्यूशन, एसएलए, एम्प्लॉयी एलोकेशन डिटेल्स, डीपीआर और प्रथम सर्विस इनवॉइस सहित दस्तावेजों का प्रावधान है। मौजूदा जीसीसी में नई प्रवृत्तियाँ और रोजगार जोड़ने के लिए भी विस्तार की मंजूरी संबंधित बोर्ड रिजोल्यूशन, अतिरिक्त प्रवृत्तियों के लिए एसएलए, डीपीआर और आवश्यक निवेश तथा कर्मचारियों की विवरण प्रस्तुत करना होगा।

कैपेक्स-ओपेक्स सहित विभिन्न खर्चों को आवरित करती सहायता

जीसीसी पॉलिसी के तहत एलिजिबल कैपेक्स एक्सपेंडिचर में बिल्डिंग का निर्माण अथवा खरीद, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग हार्डवेयर और अन्य संबंधित फिक्स्ड एसेट्स के खर्च का समावेश होता है। जमीन का खर्च इसमें शामिल नहीं है। हालांकि; जमीन या ऑफिस स्पेस के लीज, सेल या ट्रांसफर के लिए चुकाई गई स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस तथा कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट के लिए उपकरणों की खरीद पर हुआ खर्च पात्र हो सकता है।

फर्नीचर, फिक्स्चर्स, रेनोवेशन, सिविल वर्क, इंटीरियर डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिकल फिक्स्चर्स, एचवीएसी इक्विपमेंट तथा जीसीसी के लिए आवश्यक अन्य प्लांट और मशीनरी का खर्च भी आधारभूत दस्तावेजों के आधार पर गणना में लिया जा सकता है। नए जीसीसी के लिए कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने की तारीख से और मौजूदा जीसीसी के विस्तार के लिए एक्सपैंशन एप्लिकेशन की तारीख से दो वर्ष तक का संबंधित जीएफसीआई निवेश पात्र खर्च में शामिल किया जा सकता है।

क्लेम के लिए समयसीमा और दस्तावेज जाँच

कैपेक्स क्लेम एलिजिबल पीरियड पूर्ण होने के बाद एक वर्ष के भीतर फाइनेंशियल ईयर के अनुसार प्रस्तुत करना होगा। ओपेक्स का प्रथम क्लेम मंथ ऑफ एलिजिबिलिटी से शुरू होने वाले आगामी दो क्वार्टर्स में और उसके बाद के क्लेम प्रत्येक आगामी क्वार्टर पूर्ण होने से पहले प्रस्तुत करने होंगे। स्पेशल इंसेंटिव और क्वालिटी सर्टिफिकेशन के वार्षिक क्लेम आगामी फाइनेंशियल ईयर पूर्ण होने से पहले सबमिट करने होंगे। विलंब के दिनों के आधार पर इंसेंटिव की गणना प्रो-राटा के आधार पर की जाएगी।

क्लेम की प्रक्रिया के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉरपोरेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बोर्ड रिजोल्यूशन, एसएलए, सर्टिफाइड डीपीआर, कर्मचारियों का विवरण, फर्स्ट सर्विस इनवॉइस, इन्वेस्टमेंट इनवॉइस, सीए सर्टिफाइड क्लेम समरी तथा जीएफसीआई और वार्षिक ऑपरेटिंग खर्च का सीए सर्टिफिकेट सहित दस्तावेजी चेकलिस्ट निर्धारित की गई है। जीसीसी द्वारा पेरेंट अथवा ग्रुप कंपनी को ही सेवाएँ प्रदान की जाती होने की बात भी जाँच की जाएगी।

आवेदनों की जाँच के दौरान सत्ताधिकारी जरूरत के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज या स्पष्टीकरण माँग सकेगा, जो निर्धारित समयसीमा में प्रस्तुत करने होंगे। इस प्रकार; नई ऑपरेशनल गाइडलाइंस द्वारा जीसीसी पॉलिसी 2025-30 के अमल को स्पष्ट प्रक्रिया, डिजिटल सुविधा और दस्तावेज आधारित जाँच का ढाँचा मिला है, जो राज्य में नए जीसीसी की स्थापना और मौजूदा सेंटर के विस्तार के लिए व्यवस्थित मार्ग प्रदान करेगा।

मंडल रेल अस्पताल, भावनगर में HPV टीकाकरण अभियान का सफल आयोजन, HPV संक्रमण से बचाव एवं सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने की पहल

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में महिला स्वास्थ्य एवं निवारक चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 03 अक्टूबर, 2026 को मंडल रेल अस्पताल, भावनगर में HPV (Human Papillomavirus) टीकाकरण अभियान का सफल आयोजन किया गया। यह अभियान मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर मंडल श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। अभियान का उद्देश्य HPV संक्रमण से बचाव, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम तथा महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना रहा।

अभियान के दौरान कुल 59 HPV वैक्सीन डोज प्रदान की गईं। इनमें 14 लाभार्थियों को प्रथम डोज तथा 45 लाभार्थियों को द्वितीय डोज दी गई। टीकाकरण के साथ-साथ लाभार्थियों को HPV संक्रमण से बचाव, टीकाकरण के महत्व तथा आगामी डोज की समय-सारणी के संबंध में आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षा एवं परामर्श भी प्रदान किया गया।

इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि HPV टीकाकरण जैसे निवारक स्वास्थ्य अभियानों के माध्यम से रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवारों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा गंभीर बीमारियों की रोकथाम में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।

अभियान के सफल आयोजन में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार के प्रभावी नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं निरंतर प्रोत्साहन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभियान का आयोजन एवं समन्वय श्री अमृत मरेठा, मुख्य नर्सिंग अधीक्षक द्वारा किया गया। उन्होंने लाभार्थियों को HPV टीकाकरण के लाभ, संक्रमण से बचाव के उपायों तथा टीकाकरण की आवश्यक जानकारी प्रदान की और पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित एवं सुचारु रूप से संपन्न कराया।

मंडल रेल अस्पताल, भावनगर द्वारा इस अभियान के माध्यम से “रोकथाम ही बेहतर स्वास्थ्य की कुंजी है” का संदेश प्रभावी रूप से प्रसारित किया गया। यह पहल रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिए निवारक, जागरूकतापरक एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भावनगर मंडल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

यात्रियों की सुख-सुविधा में होगी वृद्धि

राज्यभर के एसटी बस स्टेशनों में ‘टॉयलेट ब्लॉक अपग्रेडेशन’ के लिए विशेष ड्राइव शुरू

राज्य के 56 बस स्टेशनों के टॉयलेट ब्लॉक का जरूरत के अनुसार रिन्यूएशन और रिपेयरिंग किया जाएगा

गांधीनगर : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के निर्देश से राज्य के एसटी बस स्टेशनों पर यात्रियों को अधिक बेहतर और आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए गुजरात राज्य मार्ग परिवहन निगम द्वारा एक महत्वपूर्ण अभियान का शुभारंभ किया गया है। यात्रा के दौरान नागरिकों को स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए निगम द्वारा राज्य के 56 बस स्टेशनों के टॉयलेट ब्लॉक रिन्यूएशन और रिपेयरिंग अभियान का आयोजन किया गया है।

एसटी निगम द्वारा पूरे राज्य में कुल 56 बस स्टेशनों पर रिपेयरिंग और टॉयलेट ब्लॉक अपग्रेडेशन का कार्य शुरू किया गया है। जिसमें से अब तक 6 बस स्टेशनों पर रिपेयरिंग का कार्य पूर्ण किया गया है। जिसमें सावरकुंडला, वांसदा, धंधुका, उमराळा, पालिताणा और ढसा बस स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा; 17 बस स्टेशनों पर कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। शेष 33 बस स्टेशनों पर रिपेयरिंग का कार्य आगामी 8 से 12 महीनों के भीतर पूर्ण कर देने की योजना है।

इस विशेष ड्राइव के पीछे मुख्य उद्देश्य यात्रियों को स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद और आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। पहले किए गए सर्वे के आधार पर एसटी निगम ने ‘बस स्टेशन बेसिक फैसिलिटी अपग्रेडेशन प्लान’ तैयार किया था। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बस स्टेशन पर पर्याप्त स्वच्छता और सुविधाएँ होना अनिवार्य है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जहाँ जरूरत महसूस हुई है; ऐसे टॉयलेट ब्लॉक्स का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया गया है।

इस अभियान के तहत टॉयलेट ब्लॉक्स में प्लंबिंग, नए यूरिनल्स और डब्ल्यूसी पैन बदलना, खिड़की-दरवाजों का रिप्लेसमेंट, आकर्षक फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, मजबूत ड्रेनेज सिस्टम और कलरकाम जैसे कार्य किए जाएँगे। इस अपग्रेडेशन के दौरान महिला यात्रियों को ध्यान में रखते हुए स्थान की स्थिति के अनुसार अनुमानित 25 यूरिनल्स, 20 जनरल डब्ल्यूसी और लगभग 25 महिला डब्ल्यूसी बढ़ाने की योजना है।

इसके अलावा; यात्री इन्फ्रास्ट्रक्चर या स्वच्छता संबंधी शिकायतें रियल-टाइम में दर्ज करा सकें; इसके लिए सभी बस स्टेशनों पर क्यूआर कोड आधारित ‘यात्री सेवा सेतु’ एप्लिकेशन भी कार्यरत किया जाएगा।

इस ड्राइव के सफल क्रियान्वयन से राज्य के लाखों दैनिक यात्रियों की सुविधा में वृद्धि होगी और एसटी बस स्टेशन अधिक स्वच्छ तथा लोकोपयोगी बनेंगे।

वीकेंड पर पर्यटकों से गुलजार शिमला, सड़कों पर लगा जाम ; होटलों की ऑक्यूपेंसी 80 फीसदी

शिमला। गांधी जयंती की छुट्टी और सप्ताहांत का एक साथ संयोग होने से राजधानी शिमला में शनिवार को पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही शहर के प्रवेश मार्गों पर वाहनों की संख्या बढ़ने लगी और दोपहर तक प्रमुख सड़कों पर यातायात का दबाव साफ दिखाई देने लगा। सर्कुलर रोड पर लिफ्ट से लेकर टॉलैंड तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं, जबकि विधानसभा से बालूगंज के बीच भी कई बार यातायात की रफ्तार धीमी हुई। पर्यटकों की बढ़ी संख्या का असर पार्किंग स्थलों पर भी पड़ा और कई स्थानों पर वाहन खड़े करने के लिए जगह तलाशना मुश्किल रहा। दूसरी ओर रिज मैदान और माल रोड पर दिनभर सैलानियों की चहल-पहल बनी रही। पर्यटकों की इस बढ़ी आमद का सीधा लाभ होटल कारोबार को मिला और शहर के होटलों में ऑक्यूपेंसी करीब 80 प्रतिशत तक पहुंच गई।

छुट्टी और सप्ताहांत को देखते हुए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक निजी वाहनों और टैक्सियों से शिमला पहुंचे। सुबह के समय वाहनों का दबाव अपेक्षाकृत कम रहा, लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ा, शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात घना होता गया। सर्कुलर रोड पर स्थिति उस समय अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई जब लिफ्ट के समीप पार्किंग स्थल करीब 11 बजे वाहनों से भर गया। इसके बाद पार्किंग की तलाश में आने वाले वाहनों की कतार टॉलैंड तक पहुंच गई। कई वाहन चालकों को सड़क किनारे पार्किंग की जगह मिलने का इंतजार करना पड़ा, जिससे यातायात की गति प्रभावित हुई।

शिमला आने वाले पर्यटकों का सबसे अधिक जमावड़ा रिज मैदान और माल रोड पर दिखाई दिया। छुट्टी के कारण परिवारों और युवाओं की बड़ी संख्या यहां घूमती नजर आई। मौसम अनुकूल होने से पर्यटकों ने शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का रुख किया। माल रोड पर दिनभर लोगों की आवाजाही बनी रही, जबकि रिज मैदान पर भी पर्यटकों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक रही। पर्यटकों की भीड़ के साथ टैक्सियों और निजी वाहनों की आवाजाही बढ़ने से शहर की पार्किंग व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा।

शहर के आसपास के पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले मार्गों पर भी वाहनों की संख्या में इजाफा हुआ। कुफरी और आसपास के पर्यटन क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहनों के कारण ढली क्षेत्र में यातायात का दबाव और बढ़ गया। यहां सड़क पर टारिंग का काम भी चल रहा था, जिससे स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई। कुफरी से भट्टाकुफर के बीच वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और कई वाहन चालकों को यह दूरी तय करने में करीब एक से डेढ़ घंटे तक का समय लगा। सामान्य दिनों में अपेक्षाकृत कम समय में तय होने वाला यह मार्ग शनिवार को जाम के कारण लंबा हो गया।

ढली क्षेत्र में यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। यातायात को सुचारु रखने के लिए कुछ वाहनों को ढली बाईपास की ओर मोड़ा गया। पुलिसकर्मी प्रमुख चौराहों और दबाव वाले स्थानों पर तैनात रहे और वाहनों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे। सड़क पर चल रहे निर्माण और टारिंग कार्य के कारण यातायात प्रबंधन की चुनौती और बढ़ गई थी। पर्यटकों की संख्या को देखते हुए पुलिस ने प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने का प्रयास किया।

शिमला में पर्यटकों की बढ़ी आमद का सकारात्मक असर पर्यटन कारोबार पर दिखाई दिया। शहर के होटल कारोबारियों के अनुसार, सप्ताहांत और गांधी जयंती की छुट्टी के कारण होटल ऑक्यूपेंसी करीब 80 प्रतिशत तक पहुंच गई। लंबे सप्ताहांत और मौसम खुलने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से होटल, टैक्सी, रेस्तरां और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबारियों को राहत मिली है। पर्यटन कारोबारी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी मौसम अनुकूल रहने पर पर्यटकों की संख्या बनी रह सकती है।

होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़ने के साथ शहर के रेस्तरां और बाजारों में भी सामान्य दिनों की तुलना में अधिक गतिविधि देखने को मिली। माल रोड और रिज के आसपास पर्यटकों की आवाजाही देर शाम तक बनी रही। स्थानीय दुकानदारों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए छुट्टी का यह सप्ताहांत कारोबार बढ़ाने वाला रहा। हालांकि, पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ यातायात और पार्किंग की समस्या ने प्रशासन के सामने शहरी प्रबंधन की चुनौती भी सामने रखी।

इसी बीच भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता प्यार सिंह कंवर ने शिमला की यातायात व्यवस्था को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती जैसे सार्वजनिक अवकाश और सप्ताहांत के दौरान शिमला में पर्यटकों की संख्या बढ़ना पहले से अनुमानित रहता है। ऐसे में यातायात प्रबंधन के लिए पहले से विशेष योजना तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने प्रमुख पर्यटन स्थलों और यातायात दबाव वाले मार्गों पर पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती की मांग की।

कंवर ने यह भी कहा कि पर्यटन सीजन और छुट्टियों के दौरान सड़क मरम्मत तथा टारिंग जैसे कार्यों को इस तरह से निर्धारित किया जाना चाहिए कि यातायात पर न्यूनतम असर पड़े। उनके अनुसार, जब पर्यटकों की संख्या अधिक हो, तब मुख्य पर्यटन मार्गों पर निर्माण कार्य होने से जाम की समस्या और गंभीर हो जाती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि सड़क कार्य कम यातायात वाले समय में कराया जाए और पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही के अनुरूप यातायात व्यवस्था को पहले से मजबूत किया जाए।

शनिवार की स्थिति ने एक बार फिर यह दिखाया कि शिमला जैसे पहाड़ी पर्यटन शहर में छुट्टियों के दौरान बढ़ने वाला पर्यटक दबाव यातायात और पार्किंग व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। एक ओर पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबार को गति मिलती है, वहीं दूसरी ओर सीमित सड़क और पार्किंग क्षमता के कारण शहर में जाम की समस्या बढ़ जाती है।

ईरान युद्ध पर ट्रंप का दावा, चुनाव के बाद संघर्ष खत्म होने की उम्मीद; तेल कीमतों में बड़ी गिरावट के संकेत

नई दिल्ली। ईरान के साथ जारी संघर्ष को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। अलबामा के मोबाइल में 2 अक्टूबर को चुनावी रैली के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध बहुत जल्द समाप्त हो सकता है और संभव है कि नवंबर में होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के तुरंत बाद संघर्ष का अंत हो जाए। उन्होंने यह भी दावा किया कि युद्ध खत्म होते ही कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि, ट्रंप का यह बयान अभी किसी युद्धविराम या शांति समझौते की आधिकारिक घोषणा नहीं है। इसके उलट, हाल के घटनाक्रमों में अमेरिका की ओर से मध्य-पूर्व में अतिरिक्त सैन्य ताकत भेजे जाने की खबरें सामने आई हैं, जिससे संघर्ष के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना रही है। उन्होंने दावा किया कि इस मोर्चे पर अमेरिका अपने उद्देश्य में सफल रहा है। ट्रंप के अनुसार, अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से ईरान को भारी नुकसान हुआ है और वहां की बुनियादी संरचना को दोबारा खड़ा करने में लंबा समय लग सकता है। हालांकि, ईरान के साथ संघर्ष के वास्तविक परिणाम और आगे की रणनीति को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इसी बीच ट्रंप ने यह संकेत भी दिया है कि चुनाव के बाद सैन्य कार्रवाई बढ़ाने का विकल्प खुला है।

ट्रंप के युद्ध जल्द समाप्त होने के दावे का सबसे बड़ा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। ईरान संघर्ष के कारण कच्चे तेल और खासकर डीजल की आपूर्ति को लेकर बाजार में चिंता बनी हुई है। ऊर्जा कीमतों पर दबाव कम करने के लिए जी-7 देशों ने आपात भंडार से करीब 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल जारी करने पर सहमति जताई है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने कहा कि इस घोषणा के बाद तेल की कीमतों में करीब पांच डॉलर की गिरावट आई है।

तेल बाजार के लिए ईरान संघर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि खाड़ी क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख केंद्र है। संघर्ष के दौरान आपूर्ति मार्गों और खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर लगातार चिंता बनी रही है। इस क्षेत्र से गुजरने वाली ऊर्जा आपूर्ति में किसी बड़े व्यवधान का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर पड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका और उसके सहयोगी देश रणनीतिक भंडार का इस्तेमाल कर बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी-7 की ओर से भंडार जारी करने का निर्णय इसी दबाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

हालांकि, एक तरफ तेल कीमतों में गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सैन्य गतिविधियां इस बात की ओर भी इशारा कर रही हैं कि वाशिंगटन ने ईरान के मोर्चे पर अपने विकल्प बंद नहीं किए हैं। अमेरिका ने यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और यूएसएस माकिन आइलैंड एम्फीबियस ग्रुप को मध्य-पूर्व की ओर भेजा है। इन समूहों में 7,000 से अधिक नौसैनिक और करीब 2,000 मरीन शामिल हैं। इनके पहुंचने के बाद क्षेत्र में तीन अमेरिकी विमानवाहक पोत समूहों की मौजूदगी हो सकती है और अमेरिकी नौसैनिकों तथा मरीन की कुल संख्या 20 हजार से अधिक होने का अनुमान है।

अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बढ़ने का घटनाक्रम ट्रंप के युद्ध समाप्त होने के दावे को और अधिक जटिल बनाता है। एक ओर राष्ट्रपति संघर्ष के जल्द खत्म होने की संभावना जता रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिकी प्रशासन सैन्य विकल्पों को मजबूत कर रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप ने ईरान की ओर से रखे गए हालिया युद्धविराम प्रस्ताव को पर्याप्त नहीं माना है और चुनाव के बाद ईरान पर फिर से बड़े पैमाने पर हमले की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि नवंबर के मध्यावधि चुनाव के बाद संघर्ष की दिशा किसी भी ओर जा सकती है।

ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक स्तर पर भी रास्ता तलाशने की कोशिश जारी है। युद्धविराम और बातचीत के प्रस्तावों को लेकर दोनों पक्षों के बीच संपर्क की संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई स्थायी समझौता सामने नहीं आया है जिससे संघर्ष पूरी तरह समाप्त होने की पुष्टि हो सके। होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने, परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी और सैन्य कार्रवाई रोकने जैसे मुद्दे बातचीत में महत्वपूर्ण बने हुए हैं। ट्रंप ने ईरान की ओर से आए प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज किया है कि वह उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप पर्याप्त नहीं था।

इस बीच अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार की नजर अमेरिकी सैन्य रणनीति और ईरान के साथ संभावित बातचीत दोनों पर टिकी हुई है। यदि संघर्ष वास्तव में समाप्त होता है और तेल आपूर्ति पर जोखिम कम होता है तो कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट संभव है। इससे पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर भी राहत का दबाव बन सकता है। इसके विपरीत, यदि चुनाव के बाद अमेरिका फिर से बड़े सैन्य अभियान की ओर बढ़ता है या ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होती है तो बाजार में कीमतों में दोबारा तेजी आ सकती है।

67वीं अखिल भारतीय अंतर–रेलवे कुश्ती चैंपियनशिप में पश्चिम रेलवे के पहलवानों का शानदार प्रदर्शन

वाराणसी में आयोजित 67वीं अखिल भारतीय अंतर-रेलवे कुश्ती चैंपियनशिप में पश्चिम रेलवे के पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। पूरी चैंपियनशिप के दौरान आत्मविश्वास, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए पश्चिम रेलवे के पहलवानों ने ग्रीको-रोमन एवं फ्रीस्टाइल दोनों वर्गों में 'प्रथम टीम ट्रॉफी' जीतकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम रेलवे के पहलवानों ने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 11 कांस्य पदकों सहित कुल 19 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। पहलवानों ने अपने-अपने मुकाबलों में उत्कृष्ट कौशल एवं जुझारू भावना का प्रदर्शन करते हुए मैट पर अपना दबदबा बनाए रखा।

ग्रीको-रोमन वर्ग में संजीव (55 किग्रा) एवं उत्तम राणा (130 किग्रा) ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि रुपिन (63 किग्रा), आकाश पूनिया (72 किग्रा) एवं रोहित दहिया (82 किग्रा) ने रजत पदक हासिल किए। मोहित नरवाल (60 किग्रा), सचिन (67 किग्रा), अनुज दहिया (77 किग्रा), मनोज कुमार (87 किग्रा) एवं नितेश कुमार (97 किग्रा) ने कांस्य पदक जीते।

फ्रीस्टाइल वर्ग में विजय पाटिल (61 किग्रा), सौरभ सहरावत (74 किग्रा) एवं प्रवीण कुमार (97 किग्रा) ने स्वर्ण पदक जीते। सरवर्ण कौशल (57 किग्रा), अजय कुमार (65 किग्रा), विजय मलिक (70 किग्रा), परमित (86 किग्रा), आकाश (92 किग्रा) एवं अमन राठी (125 किग्रा) ने कांस्य पदक हासिल किए।

ग्रीको-रोमन एवं फ्रीस्टाइल दोनों वर्गों में शानदार पदक तालिका तथा 'प्रथम टीम' ट्रॉफी जीतना पश्चिम रेलवे की कुश्ती टीम के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। पश्चिम रेलवे को पूरी कुश्ती टीम पर गर्व है, जिसने संगठन के लिए गौरव एवं सम्मान अर्जित किया है।

संसदीय स्थायी समितियों में बड़ा फेरबदल, कई अध्यक्ष बदले; कीर्ति आजाद की जगह काकोली घोष दस्तीदार

नई दिल्ली। संसद की विभाग-संबंधी स्थायी समितियों के अध्यक्षों में बड़ा फेरबदल किया गया है। 24 स्थायी समितियों के वार्षिक पुनर्गठन के तहत कुछ समितियों की कमान नए अध्यक्षों को सौंपी गई है, जबकि अधिकांश समितियों के मौजूदा अध्यक्षों को जिम्मेदारी पर बरकरार रखा गया है। इस बदलाव में रसायन एवं उर्वरक संबंधी समिति विशेष रूप से चर्चा में है, जहां तृणमूल कांग्रेस के कीर्ति आजाद की जगह काकोली घोष दस्तीदार को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा वाणिज्य संबंधी समिति की अध्यक्षता भी बदली गई है और भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी को यह जिम्मेदारी मिली है।

संसदीय समितियों का पुनर्गठन 26 सितंबर से प्रभावी माना गया है। नई व्यवस्था में रेलवे संबंधी समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता को सौंपी गई है। रक्षा संबंधी समिति की जिम्मेदारी राधा मोहन सिंह के पास बरकरार रखी गई है। इसी तरह जल संसाधन संबंधी समिति की अध्यक्षता राजीव प्रताप रूडी को और वित्त संबंधी समिति की कमान भर्तृहरि महताब को दी गई है। संसदीय समितियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की समीक्षा करने, सरकारी नीतियों पर विचार करने और संसद को अपनी सिफारिशें देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश मामलों से संबंधित स्थायी समिति के अध्यक्ष पद पर बनाए रखा गया है। इसके अलावा सप्तगिरी उलाका को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज समिति तथा चरणजीत सिंह चन्नी को कृषि संबंधी समिति की जिम्मेदारी दोबारा दी गई है। जदयू के संजय कुमार झा भी परिवहन संबंधी समिति के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। इस तरह कई महत्वपूर्ण समितियों में नेतृत्व की निरंतरता कायम रखी गई है।

भाजपा के निशिकांत दुबे को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति की अध्यक्षता पर बरकरार रखा गया है। अनुराग ठाकुर कोयला, खान एवं इस्पात संबंधी समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे, जबकि श्रीरंग बारणे को ऊर्जा संबंधी समिति की जिम्मेदारी जारी रखी गई है। रक्षा समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह के पद पर बने रहने की पुष्टि संसदीय समिति से संबंधित उपलब्ध जानकारी में भी होती है।

रसायन एवं उर्वरक समिति में हुआ बदलाव इस पुनर्गठन का प्रमुख पहलू है। पहले इस समिति की अध्यक्षता कीर्ति आजाद के पास थी, लेकिन अब काकोली घोष दस्तीदार को इसकी कमान दी गई है। डिजिटल संसद के रिकॉर्ड के अनुसार काकोली घोष दस्तीदार पश्चिम बंगाल की बारासात लोकसभा सीट से सांसद हैं।

संसदीय समितियों में होने वाला यह वार्षिक पुनर्गठन संसद के कामकाज का नियमित हिस्सा है, लेकिन कुछ प्रमुख बदलावों का राजनीतिक और संसदीय स्तर पर अलग महत्व भी होता है। इस बार छह समितियों के अध्यक्ष पदों में बदलाव की रिपोर्ट सामने आई है। इनमें वाणिज्य और रसायन एवं उर्वरक संबंधी समितियां भी शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस के लिए यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी के पास पहले इन दोनों समितियों की अध्यक्षता थी। वाणिज्य संबंधी समिति की जिम्मेदारी अब भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी को दी गई है। इससे पहले यह समिति तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन की अध्यक्षता में काम कर रही थी। इस बदलाव के साथ तृणमूल कांग्रेस की दोनों समिति अध्यक्षताएं बदल गई हैं। संसदीय समिति व्यवस्था में विभिन्न दलों को प्रतिनिधित्व देने की परंपरा के बीच अध्यक्ष पदों में होने वाले बदलावों पर राजनीतिक दलों की भी नजर रहती है।

स्थायी समितियों की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि सदन की कार्यवाही के अलावा इनमें मंत्रालयों के कामकाज, बजट, नीतियों और योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की जाती है। समितियां विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों और संबंधित पक्षों से जानकारी लेकर विभिन्न विषयों पर विचार करती हैं तथा अपनी रिपोर्ट संसद के समक्ष रखती हैं। इस प्रक्रिया के जरिए विधायी और प्रशासनिक कामकाज की संसदीय निगरानी को मजबूती मिलती है।

इस पुनर्गठन के बाद अधिकांश समितियों में पुराने अध्यक्षों को ही जिम्मेदारी सौंपे जाने से कई क्षेत्रों में काम की निरंतरता बनी रहेगी। वहीं जिन समितियों में नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, वहां आने वाले समय में उनके नेतृत्व में समिति की बैठकों और मंत्रालयों से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा आगे बढ़ेगी। संसद की वेबसाइट पर विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों में कृषि, रसायन एवं उर्वरक, कोयला-खान-इस्पात, रक्षा, ऊर्जा, विदेश मामले, वित्त, संचार, श्रम, पेट्रोलियम, रेलवे, ग्रामीण विकास और जल संसाधन सहित विभिन्न समितियां सूचीबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री का 'स्वागत' ऑनलाइन कार्यक्रम बना सामान्य ग्रामीण नागरिक की प्रस्तुति के त्वरित निवारण का सकारात्मक उपक्रम

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 'जो कहना वह करना' की कार्य संस्कृति को साकार किया

गांधीनगर : सामान्य नागरिकों की प्रस्तुतियों एवं समस्याओं के प्रभावी निवारण के रूप में 'स्वागत' ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम सटीक और असरकारक माध्यम साबित हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में अगस्त-26 महीने के राज्य 'स्वागत' कार्यक्रम में मिली आदिजाति क्षेत्र के ग्रामीण नागरिक की गाँव की पक्की सड़क बनाने की प्रस्तुति का त्वरित प्रतिसाद दिया है।

मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में साबरकाँठा के विजयनगर तहसील के भटेला गाँव के कच्चे रास्ते को मेटल सतह से डामर सड़क बनाने के कार्यों के लिए 99.50 लाख रुपए मंजूर किए हैं।

स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवन्सीस बाय एप्लिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी-'स्वागत' का यह जन शिकायत निवारण उपक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में अपने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान शुरू करवाया था।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल भी उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को राज्य 'स्वागत' कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित रहकर नागरिकों की प्रस्तुतियाँ सुनने के साथ-साथ उसके उचित निराकरण की सूचनाएँ भी संबंधित विभागों एवं जिला प्रशासन को देते रहते हैं।

अगस्त-26 के राज्य 'स्वागत' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष साबरकाँठा के विजयनगर तहसील के नवागाम धनेला के नागरिक श्री तुषारभाई ने भटेला गाँव के मेटल रास्ते का काम पूरा कर डामर सतह का पक्की सड़क बनाने के लिए प्रस्तुति की थी।

मुख्यमंत्री ने सड़क एवं भवन विभाग और जिला कलेक्टर से इस रास्ते के काम के बारे में 'स्वागत' के दौरान ही विवरण प्राप्त करके पॉजिटिव एप्रोच अपनाकर यह काम तीन महीनों में पूरा कर देने की स्पष्ट सूचनाएँ दी थीं।

इतना ही नहीं; मुख्यमंत्री ने यह काम पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय मंजूरियाँ भी सड़क एवं भवन विभाग को देकर 99.50 लाख रुपए इमरजेंसी टेंडर रोड के तहत मंजूर किए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनसमस्याओं के निवारण और लोकहित के कार्यों के लिए 'जो कहना वह करना' की कार्य संस्कृति विकसित की है, उसका स्वयं स्पष्ट उदाहरण मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने साबरकाँठा के आदिजाति क्षेत्र के विजयनगर के भटेला गाँव के पक्के रास्ते की मंजूरी देकर प्रस्तुत किया है।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने सूरत सर्किट हाउस में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया

उप मुख्यमंत्री ने नागरिकों के समस्याएँ एवं प्रस्तुतियों को सुनकर तुरंत ही समाधान लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए

गांधीनगर : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने शनिवार को सूरत सर्किट हाउस में विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान सूरत शहर एवं जिले से बड़ी संख्या में आए नागरिकों की प्रस्तुतियां प्रत्यक्ष रूप से सुनीं। प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाने, सरकार और प्रशासन को लोगों के अधिक निकट लाने तथा आम जनता के समस्याओं का त्वरित निराकरण लाने के उद्देश्य से जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गत दिनों में अपने समस्याओं एवं प्रस्तुतियों का सकारात्मक समाधान पाने वाले आवेदकों ने उप मुख्यमंत्री से प्रत्यक्ष रूप से मिलकर हृदयपूर्वक आभार व्यक्त किया ।

इस जनसंपर्क के दौरान उप मुख्यमंत्री ने उत्साहपूर्वक एक-एक कर नागरिकों और आवेदकों से मिलकर उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों, स्थानीय प्रशासन से संबंधित समस्याओं तथा विकासोन्मुखी प्रस्तुतियों को ध्यानपूर्वक सुना। नागरिकों को

सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान आए; इसके लिए उप मुख्यमंत्री ने उपस्थित संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों को टेलीफोनिक सूचनाएँ देकर शीघ्र कार्रवाई करने का आदेश दिया।

सरकार की प्रजानोन्मुखी एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली के भागरूप आयोजित इस जनसंपर्क कार्यक्रम में उपस्थित सूरतवासियों ने उप मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्या स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत की और सरकार द्वारा उनके समस्याओं को प्राथमिकता देकर सकारात्मक अभिगम अपनाने के लिए खुशी व्यक्त की। उप मुख्यमंत्री के प्रजानोन्मुखी दृष्टिकोण से नागरिकों में सरकार और प्रशासन के प्रति विश्वास अधिक दृढ़ बना।

सितंबर 2026 में अहमदाबाद मंडल का शानदार प्रदर्शन : 852 करोड़ की कुल आय, यात्री राजस्व ने बनाया सर्वकालिक रिकॉर्ड

अहमदाबादः पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने सितंबर 2026 में वाणिज्यिक एवं यात्री सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए माल भाड़ा, यात्री एवं पार्सल आय से लगभग 852 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। इसमें 636 करोड़ माल भाड़ा आय, 208.60 करोड़ यात्री आय तथा 7.40 करोड़ पार्सल आय शामिल है। सितंबर माह में यात्री आय में पिछले वर्ष की तुलना में 34.5% की वृद्धि दर्ज की गई और 208.60 करोड़ की यात्री आय मंडल के इतिहास में सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ मासिक यात्री आय रही।

मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद, श्री वेद प्रकाश ने इस शानदार प्रदर्शन पर मंडल के वाणिज्य, परिचालन एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए उनके निरंतर प्रयासों की सराहना की।

1. वित्तीय एवं वाणिज्यिक प्रदर्शन

अहमदाबाद मंडल ने सितंबर 2026 में विभिन्न क्षेत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की:

- माल भाड़ा आयः 636.08 करोड़, जो सितंबर 2025 की 595.16 करोड़ की तुलना में 6.88% अधिक है।
- यात्री आयः 208.60 करोड़, जो सितंबर 2025 की 155.05 करोड़ की तुलना में 34.54% अधिक है तथा यह मंडल के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ मासिक यात्री आय है।
- पार्सल आयः 7.40 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक अधिक है।

2. माल आय में नए रिकॉर्ड और उपलब्धियां

सितंबर माह में मंडल के विभिन्न गुड्स शेड एवं टर्मिनलों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया:

- M/s Western Carriers India Pvt. Ltd. देवलिया (WCGD) ने 4.87 करोड़ की सर्वश्रेष्ठ मासिक माल आय दर्ज की। इससे पहले का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जुलाई 2026 में 4.55 करोड़ था।
- नालिया गुड्स शेड ने 4.75 करोड़ की सर्वश्रेष्ठ मासिक माल आय दर्ज की, जबकि पिछला सर्वश्रेष्ठ 3.96 करोड़ जुलाई 2026 में था।
- समाखियाली गुड्स शेड ने 8.64 करोड़ की सर्वश्रेष्ठ मासिक माल आय दर्ज की। इससे पहले का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मार्च 2026 में 8.49 करोड़ था।
- कांडला पोर्ट गुड्स शेड को 30 सितंबर 2026 से कंटेनर ट्रैफिक के लिए कंटेनर रेल टर्मिनल (CRT) के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा यहां चौबीसों घंटे कार्य किया जाएगा।
- नरोडा गुड्स शेड को 16 सितंबर 2026 से कांकड़िया के वैकल्पिक गुड्स शेड के रूप में अधिसूचित किया गया है।

3. नए कमोडिटी, नए गंतव्य और नए ग्राहक

मंडल द्वारा नए व्यापारिक अवसरों को विकसित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गईं:

- M/s Shri Renuka Sugar Limited (SRSL) द्वारा गांधीधाम से विभिन्न गंतव्यों के लिए चीनी की 5 रेक BCN वैगनों में लोड की गईं, जिससे 2.85 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।
- दक्षिण पश्चिम रेलवे के देवणगोंथी, उत्तर रेलवे के चिलबिला जंक्शन, पटली एवं पलवल, उत्तर पश्चिम रेलवे के बावल, ईस्ट कोस्ट रेलवे के सुकिंदा रोड, सेंट्रल रेलवे के मिराज तथा DFCR के न्यू सरधना सहित विभिन्न नए गंतव्यों के लिए कंटेनर, उर्वरक एवं अन्य रेक संचालित की गईं।
- M/s DB Tradelink Pvt. Ltd. द्वारा कांडला पोर्ट डॉक रेल टर्मिनल से दाधदेवी, कोटा मंडल के लिए आयातित स्टीम कोयले की 3 रेक लोड की गईं, जिससे 2.12 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।
- M/s Railhaul Logistics Pvt. Ltd. द्वारा कांकरिया से मिर्जा, रंगिया मंडल के लिए मिश्रित कमोडिटी की 3 मिनी रेक संचालित की गईं, जिससे 97.18 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ।
- M/s Shri Khaitan Chemicals & Fertilizers Ltd. द्वारा आयातित उर्वरक की 2 मिनी रेक विभिन्न गंतव्यों के लिए लोड की गईं।
- M/s Threeline Logistics & Shipping Pvt. Ltd. द्वारा कांडला पोर्ट डॉक रेल टर्मिनल से बामनहेरी के लिए बांस पल्प की एक रेक संचालित की गई, जिससे 29.53 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ।

4. पार्सल व्यवसाय में महत्वपूर्ण उपलब्धि

- 16 एवं 17 सितंबर 2026 को पार्सल स्पेस की ई-नीलामी आयोजित की गई, जिसके माध्यम से 4 परिसंपत्तियों की सफलतापूर्वक लीजिंग की गई। इन अनुबंधों से आगामी 3 वर्षों में 3.61 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान लगभग 0.61 करोड़ का राजस्व अनुमानित है।

5. यात्री सेवाएं एवं विशेष ट्रेनें

त्योहारी एवं मेले के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए मंडल द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गईं:

- 09405/09406 असरवा–खेडब्रह्मा मेला स्पेशल का संचालन 21 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 तक भादरवी पूनम मेले की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए किया गया।
- 09465 अहमदाबाद–दरभंगा स्पेशल को अतिरिक्त दीपावली एवं छठ पूजा भीड़ के मद्देनजर 27 नवंबर 2026 तक बढ़ाया गया।
- 09088 अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल TOD स्पेशल का संचालन 10 सितंबर से 26 नवंबर 2026 तक नवरात्रि, दीपावली एवं छठ पूजा की भीड़ को देखते हुए किया गया।
- अतिरिक्त यात्री संख्या को देखते हुए 25 विशेष ट्रेन फेरे संचालित किए गए, जिनसे लगभग 0.36 लाख यात्रियों को सुविधा मिली तथा 3.02 करोड़ यात्री राजस्व प्राप्त हुआ।

6. टिकट जांच एवं डिजिटल टिकटिंग

टिकट जांच अभियान के दौरान सितंबर 2026 में विभिन्न स्तरों पर प्रभावी कार्रवाई की गई:

- 3 फोर्ट्रेस चेक में 475 मामले पकड़े गए तथा 4.56 लाख का जुर्माना वसूला गया।
- 2 एम्बुश चेक में 375 मामले पकड़े गए तथा 3.50 लाख का जुर्माना वसूला गया।
- 9 विशेष फोर्ट्रेस चेक में 1,557 मामले पकड़े गए तथा 16.54 लाख का जुर्माना वसूला गया।
- स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए लगभग 160 एंटी-लिटरिंग मामले दर्ज कर 1.27 लाख तथा 16 एंटी-स्मोकिंग मामले दर्ज कर 0.32 लाख का जुर्माना वसूला गया।

7. माल परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती

15 सितंबर 2026 को माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने शिवलखा गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (GCT) का उद्घाटन तथा भीमासर, देवलिया और चंडीसर GCT को राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही लिंच GCT की आधारशिला रखी गई।

इस अवसर पर शिवलखा से मिठापुर के लिए भारत की पहली स्टेनलेस स्टील साल्ट कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। नवनिर्मित गोपालपुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया गया, जिससे अहमदाबाद/भुज के बीच चलने वाली ट्रेनों के लिए गांधीधाम में इंजन रिवर्सल की आवश्यकता समाप्त हुई। इसके अतिरिक्त ट्रेन संख्या 22829 भुज–शालीमार एक्सप्रेस को अंजार स्टेशन पर नया निर्धारित ठहराव प्रदान किया गया।

रायका वन क्षेत्र में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 20 ढांचे ध्वस्त कर 150 कनाल जमीन कराई खाली

जम्मू। जम्मू के बाहरी इलाके रायका वन क्षेत्र के रहीम नगर में वन भूमि पर कथित अतिक्रमण के खिलाफ शनिवार को बड़ी कार्रवाई की गई। वन विभाग, वन सुरक्षा बल, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर 17 कच्ची झोपड़ियों और तीन पक्के ढांचों को ध्वस्त कर करीब 150 कनाल वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। अधिकारियों के अनुसार, इन ढांचों में अधिकांश पर रोहिंग्या परिवारों के रहने की जानकारी सामने आई थी, हालांकि कुछ स्थानीय लोग भी वहां रह रहे थे। विभाग ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाकर नहीं की गई, बल्कि वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई है।

रहीम नगर में कार्रवाई सुबह के समय शुरू हुई। मौके पर बड़ी संख्या में वन विभाग और वन सुरक्षा बल के कर्मचारी मौजूद रहे, जबकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तथा जिला प्रशासन की टीम भी तैनात रही। अधिकारियों के मुताबिक, संबंधित क्षेत्र की पहचान वन विभाग की जमीन के रूप में की गई थी और वहां बनाए गए ढांचों को अतिक्रमण की श्रेणी में रखा गया था। विभाग ने बताया कि कार्रवाई से पहले वहां रहने वाले लोगों को जमीन खाली करने के लिए कहा गया था। एक अधिकारी के अनुसार, लोगों को पहले चेतावनी दी गई और उन्हें अपने सामान को बाहर निकालने का अवसर भी दिया गया।

वन विभाग के अनुसार, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले इलाके में नोटिस और चेतावनी की प्रक्रिया अपनाई गई थी। अधिकारियों का कहना है कि संबंधित लोगों को करीब दस दिन पहले जमीन खाली करने के लिए कहा गया था। इसके बावजूद ढांचे नहीं हटाए गए, जिसके बाद संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। विभाग ने यह भी बताया कि अभियान के दौरान महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की सहायता ली गई तथा निवासियों को अपने सामान को बाहर निकालने का समय दिया गया।

कार्रवाई के दौरान कुछ प्रभावित लोगों ने प्रशासन के दावे से अलग अपनी शिकायतें भी सामने रखीं। जम्मू निवासी स्टीफन ने आरोप लगाया कि उन्हें कार्रवाई से पहले पर्याप्त सूचना नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि उनका परिवार करीब 10 से 12 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहा था और ढांचा हटाए जाने के बाद उनके सामने परिवार के साथ रहने की समस्या खड़ी हो गई है। अन्य प्रभावित परिवारों ने भी कार्रवाई के बाद अपने सामान और रहने की व्यवस्था को लेकर चिंता जताई।

रहीम नगर में हुई कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब जम्मू में वन और सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई तेज हुई है। इससे पहले भी जम्मू के अलग-अलग इलाकों में अवैध ढांचों को हटाने के अभियान चलाए गए हैं। सितंबर में नरवाल क्षेत्र में प्रशासन की ओर से जमीन खाली कराने के लिए नोटिस दिए जाने के बाद कई रोहिंग्या परिवारों द्वारा अपनी झोपड़ियां स्वयं हटाने की खबर सामने आई थी। इसके बाद रहीम नगर में वन क्षेत्र के भीतर नए ढांचों के सामने आने को लेकर प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं।

वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, रहीम नगर का संबंधित क्षेत्र करीब पांच हेक्टेयर में फैला हुआ है और यहां अतिक्रमण का विस्तृत ब्योरा तैयार किया गया है। विभाग का कहना है कि केवल उन्हीं ढांचों को हटाया गया, जिन्हें वन भूमि पर अवैध निर्माण के रूप में चिन्हित किया गया था। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि वन नियम किसी एक समुदाय के लिए अलग नहीं हैं। वन भूमि पर जहां भी अतिक्रमण पाया जाएगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि कुछ लोगों द्वारा झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों से किराया वसूले जाने की जानकारी सामने आई है। विभाग ऐसे लोगों की भूमिका की जांच कर रहा है और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस पहलू की जांच इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि वन भूमि पर अस्थायी ढांचे खड़े कर उन्हें किराये पर देने से न केवल सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला बनता है, बल्कि लंबे समय तक अनधिकृत बस्ती विकसित होने की संभावना भी बढ़ती है।

वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के बाद अब उसके संरक्षण पर भी विभाग का जोर है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, खाली कराई गई जमीन को दोबारा कब्जे से बचाने के लिए निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की योजना है। विभाग का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के बाद जमीन को वन उपयोग के लिए बहाल करने तथा दोबारा निर्माण रोकने के उपाय किए जाएंगे।

रायका वन क्षेत्र में हुई कार्रवाई को जम्मू में चल रहे व्यापक अतिक्रमण-विरोधी अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है। वन विभाग के अनुसार, जम्मू वन संभाग में इस वर्ष अब तक कई चरणों में वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है और आगे भी चिन्हित क्षेत्रों में कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग का कहना है कि वन भूमि का संरक्षण केवल पर्यावरणीय दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है।

हालांकि, इस तरह की कार्रवाई के साथ विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वास और मानवीय पहलू को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। प्रभावित लोगों की ओर से रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की गई है, जबकि प्रशासन का मुख्य जोर यह है कि वन भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में आने वाले दिनों में अतिक्रमण हटाने के साथ प्रभावित परिवारों की स्थिति और प्रशासन की आगे की नीति पर भी नजर रहेगी।